मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 23 अंक : 7

5 मार्च 2023

- देश सेवा के नाम पर स्वयं सेवा।
- अडानी मामले में मोदी का मौन, मायने क्या हैं?

क्या आजाद भारत में सबसे बड़ा स्कैम किया है अडानी ने?

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
उत्तरप्रदेश संवाददाता	वेद कुमार मौर्य

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.in

(पृष्ठ क्र.-6)

- मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी के मायने 42
- मध्यप्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में मौजूद अपार 46
- कम्पलीट बिजनेस साल्यूशन वाले फ्यूचर रेडी स्टेटट म.प्र. 50
- कैसे होगी मंहगाई कम ? 54
- श्रमिकों के लिए अभी बहुत कुछ करना है 56
- Public Relations in Banking Sector 61

अडानी
हिंडनबर्ग

मप्र विधानसभा के बजट सत्र से कांग्रेस विधायक का निलंबन...

क्या सता पक्ष से सवाल करना असंवैधानिक है?

मप्र विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के भेंट चढ़ता जा रहा है। सता और विपक्ष के बीच विभिन्न मुददों को लेकर तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। इन सबके बीच 02 मार्च के दिन तो विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। यह निलंबन सत्तापक्ष की मांग पर किया गया। सत्तापक्ष ने पटवारी पर आरोप लगाए कि वह सरकार पर गलत आरोप लगाकर संसदीय मर्यादाओं को उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस का कहना है कि वह सरकार से विभिन्न मुददों को लेकर जबाव मांग रही है और यह हमारा अधिकार है। पटवारी के निलंबन के बाद तो पूरे सदन में अब हंगामे की नौबत बन गई है। यहां सवाल उठता है कि क्या विपक्ष का सत्तापक्ष से सवाल करना असंवैधानिक है? क्या सवाल करने पर किसी विधायक को सदन से बाहर ही कर देना चाहिए? यह ऐसे सवाल है जो लौकतांत्रिक व्यवस्था में पूछा जाना लाजिमी है।

कांग्रेस का कहना है कि दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात वाला है। इससे पहले सत्तापक्ष की ओर से पटवारी के खिलाफ बार-बार झूठ बोलने को लेकर निलंबन की कार्रवाई की मांग की गई थी। जीतू पटवारी के निलंबन से पूरा विपक्ष लामबंद हो गया और इस एक्शन पर आक्रामक हो गया। इससे पहले सत्र के दौरान पटवारी ने अपने भाषण में कहा था कि प्रदेश से बाघ, शेर, घड़ियाल बाहर गए। बदले में छिपकली, बंदर, तोते लिए गए। जीतू पटवारी ने फिर कहा केवल सरकार के पैसे से बीजेपी के कायकर्ताओं को खाना खिलाया और बीजेपी कार्यालय के अंदर। पांच साल में 09 करोड़ रुपये का खाना खिलाया तो बीस साल में कितने का खिलाया होगा? बहस के दौरान पटवारी ने सरकार पर जनता के पैसों की बर्बादी के आरोप लगाये वो भी पार्टी के काम में। बहस के दौरान जीतू पटवारी ने कहा मुख्यमंत्री ने गरीब के पैसे से, कर्ज के पैसे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, वहां की मीटिंग्स में 40 करोड़ रूपये का खाना खिला दिया। यह देश का पहला मुख्यमंत्री है, जिसने सरकार के पैसे से बीजेपी कार्यालय में खाना खिलाया।

इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से ऐतराज जताया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पटवारी पर बार-बार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास में विधायकों को निलंबित करने का मामला पहली बार नहीं है। इसके पहले भी मार्च 1966 में विधानसभा उपाध्यक्ष नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, मार्च 1991 में अध्यक्ष बृजमोहन मिश्रा और फरवरी 2003 में अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी द्वारा विधायकों को निलंबित किया गया था।

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा मप्र की विधानसभा का बहुत दुखद दिन है। विधानसभा और लोकसभा का मुझे सालों का अनुभव है, पक्ष हो या विपक्ष। विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब देती है। जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कई मुद्दे उठाए। कई ऐसे मुद्दे थे, जिसका जवाब विधानसभा में दिया गया। कमलनाथ ने आगे कहा पटवारी ने कर्ज की बात उठाई। लगभग 04 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया। 75 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ब्याज लग रहा है। ये 24 हजार करोड़ रुपए प्रति साल का ब्याज है। रिजर्व बैंक ने नोटिस देकर संपत्ति की नीलामी की। हमारा सवाल है कि ये कर्ज क्यों लिया जा रहा है? बड़े-बड़े ठेके दें, इन ठेकों में एडवांस दें और उससे अपना कमीशन लें। जीतू पटवारी ने हवाई जहाज पर हुए खर्च का सवाल उठाया। इन पर जवाब देने के बजाय जीतू पटवारी पर जो कार्रवाई हुई, वो पहले से तय थी। कमलनाथ ने कहा विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, उन्होंने जीतू पटवारी का निलंबन किया। इसका मतलब ये हमारी आवाज रोकना चाहते हैं। हमें बोलने नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि इनकी बातों का खुलासा हो। ये संविधान और हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत दुखद दिन है।

विजया पाठक

क्या आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम किया है अडानी ने?

24 जनवरी 2023 को अमेरिकी रिसर्च फर्म कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने देश के प्रमुख उदयोगपति गौतम अडानी को दिन में चांद तारे दिखा दिये हैं। सवा महीने में अडानी साम्राज्य पूरी तरह हिल गया है। रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनियों के शेयर गिरने का जो सिलसिला चालू हुआ वह अभी भी रूकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस रिपोर्ट के उजागर होने के बाद अडानी ग्रुप की 10 सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में लगभग 12 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। 19 लाख करोड़ के मालिक अब सिर्फ 07 लाख करोड़ के मालिक बचे हैं। यह गिरावट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार बिकवाली आने से हुई है। कई कंपनियों के स्टॉक अपने 52 सप्ताह की ऊंचाई की तुलना में 82 प्रतिशत तक टूट गए हैं। दरअसल किसी भी व्यक्ति के लिए देश रक्षा और उसकी प्रगति सबसे अधिक अहम होता है। व्यक्ति खुद के प्रगति के साथ-साथ देश की प्रगति में योगदान देना अपना प्राथमिक कर्तव्य समझता है। हमें इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर बात चाहे धीरूभाई अंबानी की हो या फिर टाटा, बिरला जैसे उद्योगपतियों की। इन उद्योगपतियों ने अपनी प्रगति के साथ-साथ देश हित और उसकी प्रगति पर भी ध्यान दिया। लेकिन अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस पूरी धारा को ही बदल दिया। अडानी ने देश के भीतर रहकर ही देशवासियों के साथ जो धोखा किया है उसे देख यही लगता है कि अडानी ने देश हित पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने विषय में सोचा है। हिंडनबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसे देखकर यही लगता है कि अडानी ने देशहित में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचा। यही कारण है की अडानी की गलती की सजा आज पूरा देश और देश की जनता भुगतने को मजबूर है। अगर अडानी ने एक प्रतिशत भी देश हित में सोचा होता तो आज अडानी समूह की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठते और न ही देश को इतना बड़ा वित्तीय संकट होता। बताया जाता है कि गौतम अडानी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी होने के बाद प्रचार-प्रसार के लिए अरबों रुपया खर्च किया। इस रुपए के एवज में अडानी ने देश की प्रमुख खदानों, बड़े व्यवसायों को अपना बना लिया और देश में बड़ा वित्तीय भ्रष्टाचार कर उसे अंजाम दिया। जानकारों के अनुसार एक व्यवसाई को इतना अधिक बढ़ावा देना केंद्र सरकार की भी बड़ी गलती का उदाहरण है। गौतम अडानी के इस वित्तीय भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के बाद भी केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी आयकर, ईडी ने जिस हिसाब से चुप्पी साधी है उससे साफ पता चलता है कि इस पूरे खेल में कई बड़े मंत्री और इन एजेंसी के अधिकारी भी शामिल हैं और सभी की भूमिका संदेह के घेरे में है। सरकार को चाहिए कि इस सबकी भी निष्पक्ष जांच करवाए। वर्ष 2014 के पहले जो गौतम अडानी विश्व के अमीरों की सूची में टॉप 100 में भी शामिल नहीं थे, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के कुछ सालों के भीतर ही विश्व के दूसरे अमीर व्यक्ति बन गये। गौतम अडानी का हवा की गति से अमीर बनना पहले दिन से ही संदेहात्मक था लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दबाव में आकर कभी किसी जांच एजेंसी ने इस पर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कुल मिलाकर गौतम अडानी का अब सही रूप सामने आया है और गौतम अडानी सच में दो नंबरी निकले।

विजया पाठक

विश्व के अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जिस तरह से अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग ने किया है, उस रिपोर्ट ने गौतम अडानी को अर्श से फर्श पर ला पटका है। गौतम अडानी द्वारा किये गये इस घोटाले ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। अडानी के इस कारनामे के बाद राजनैतिक धुरंधरों के भी पसीने छूट गये हैं और रातों की नींद उड़ गई है। भारत में विपक्ष भी अदानी समूह को घेर रहा है। संसद में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर ये मुद्दा उठाया और अदानी समूह के वित्तीय लेनदेन की जाँच के लिए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) गठित करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ... उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दोस्ती जगजाहिर है। इनकी दोस्ती के किस्से विश्वभर में प्रसिद्ध है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया है तो मोदी की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगे है। क्या मोदी की राह पर अडानी ने फर्जी साम्राज्य स्थापित किया है।

और गौतम अडानी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा चंद लोग इस देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। हमारा पैसा और संपत्ति भी हमारी और उस पैसे से एक-एक

नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी जी बतायें कि उनका और गौतम अडानी का क्या रिश्ता है? इसके अलावा सपा, आप, टीएमसी और अन्य पार्टियों के

मामले को प्रमुखता से नहीं लिया। जबकि जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उजागर हुआ है वह निश्चित ही बहुत बड़ा एक स्केम है। जिसमें सरकार के साथ साथ देश के

लोकसभा चुनाव में मोदी के पीएम उम्मीदवार बनते ही अडानी और अंबानी ने की थी अरबों रूपये की फंडिंग

(संपत्ति) खरीद कर मोदी जी एक व्यक्ति को दे रहे हैं। उस अडानी को इतना बड़ा बना रहे हैं कि वह एक व्यक्ति आज हाथी के जितना मोटा बन गया है। वहीं कांगेस के

नेताओं ने भी मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। इन सबके बीच देश की गोदी मीडिया इस मामले पर शांत बैठी है। किसी भी टीवी चैनल या समाचार पत्र ने इस पूरे

कई लोगों का भविष्य जुड़ा है। इन सबके बीच रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंकों के अदानी समूह को दिए क़र्ज़ के बारे में जानकारी मांगी है।

निश्चित ही हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट ने अडानी समूह को झंकझोर कर रख दिया है। इस रिपोर्ट ने गौतम अडानी को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा की गई जांच के निष्कर्षो में आरोप लगाया गया है कि समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी ने पिछले तीन वर्षो में अपने मूल्य में 100 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि की है। हिंडनबर्ग द्वारा अरबपति गौतम अडानी के विशाल साम्राज्य पर एक अभूतपूर्व हमले के बाद अडानी के सभी 10 शेयरों का बाजार मूल्य

कैसे नियमों को ताक पर रखकर अडानी को पहुंचाया लाभ

गौतम अडानी की कहानी में कोयला आ गया है और विनोद अडानी भी आ गये हैं। नया सवाल यह आया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आवंटन रद्द करने के बाद भी अडानी के लिए नियमों में बदलाव किए गए ताकि उन्हें जिस खदान का ठेका मिला था उसका कारोबार चलता रहे। सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाकी के खदान बंद कर दिए गए तो एक कंपनी का खदान क्यों चलता रहा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खोजी रिपोर्ट आई है और फोर्स पत्रिका में फिर से गौतम अडानी पर रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पर आधारित जवाब भी दिया है। कहा गया है कि कोयला आवंटन नियमों के तहत हैं। अच्छी बात है कि अडानी समूह ने जवाब दिया है। रिपोर्ट इस कलेक्टिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय नीति आयोग और कोयला मंत्रालय से भी जवाब मांगा था मगर उन्हें जवाब नहीं मिला है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार गिरीश और कुमार संभव की है। रिपोर्ट अलजरीरा की वेबसाइट में छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयला खदानों को निरस्त कर दिया। यह सभी 1993 से लेकर 2010 के बीच आवंटित किए गए। हो यह रहा था कि राज्य सरकार की कंपनियों को खदान मिलता था वो कंपनियां प्रायवेट कंपनियां गुप्त ठेके के आधार पर सौंप दिया करती थी। मुनाफा प्रायवेट कंपनियों के जेब में जा रहा था। इसी कड़ी में 2008 में एक कांट्रेक्ट अडानी समूह को भी मिलता है। मगर अडानी समूह का काम रहे इसके लिए मोदी सरकार नियमों में एक अपवाद का सहारा लेती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है कि उस खदान से अदानी समूह उस खदान से 80 मिलियन टन कोयला निकल चुका है। रिपोर्टर्स ने कई दस्तावेज खंगाले हैं उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सरकार ने अकेले अडानी समूह के लिए छूट क्यों दी। सरकारी कार्यो के अध्ययन से पता चलता है कि सरकार के बड़े अफसरों ने इस डील को अनुचित बताया था। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का वादा था कि सरकार में आते ही सारे खदानों की फिर से नीलामी की जाएगी और पारदर्शी तरीके से होगी लेकिन इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नई सरकार में भी निजी कंपनियों को कॉम्पिटेटिव बिडिंग की प्रक्रिया से छूट मिलती रही है यानी टेंडर में कोई दूसरी कंपनी ना हो इसका इंतजाम और तरीके से कर दिया जाता है ताकि

पसंद की कंपनी को ठेका मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है कांग्रेस कहती है कि देश में मित्रकाल चल रहा है। 15 अगस्त 2022 के दिन प्रधानमंत्री ने लालकिले से कहा कि देश में दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक भ्रष्टाचार और दूसरा भाई भतीजावाद। क्या अदानी समूह को लेकर जो खबरें छप रही हैं वह भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के दायरे में नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री के भाषण का सार है जहां वे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। उस देश को लड़ना ही होगा हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़ेगा। हम कोशिश भी कर रहे हैं। भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य से राजनीति क्षेत्र की बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। मेरे देश के नौजवानों आपके उज्वल भविष्य के लिए आपके सपनों के लिए मैं भाई भतीजावाद लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। क्या वाकई प्रधानमंत्री भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तब तो नहीं बताना चाहिए कि आज जो खबर छपी है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। गौतम अडानी और विनोद अडानी को लेकर जो भी छप रहा है। वह क्या भाई भतीजावाद नहीं है। क्या भाई भतीजावाद में मित्रवाद नहीं आता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने केवल कोयला खदान को लेकर सवाल नहीं

आधा हो गया और कंपनी को लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। अब जबकि हिंडनबर्ग बनाम अडानी समूह की गाथा जारी है। एक सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या यह पहली बार है जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने किसी कंपनी के

उठाए। वह तो आज छपी है। 27 फरवरी को जो खबर आई थी उस पर तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि एक ही कंपनी अपनी कई कंपनियां बना ले और टेंडर भर दे और बाकी कोई दूसरी कंपनी ना आए और दूसरी कोई कंपनी न आए तो क्या भाई भतीजावाद नहीं है। 27 फरवरी की इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं जिसमें रिपोर्टर्स कलक्टिव के रिपोर्टरों ने बताया है कि आरपी संजीव गोयनका समूह की कंपनी बंगाल के कोयला खदान के लिए टेंडर में भाग लेती हैं। गोयनका समूह की ही अलग-अलग कंपनियां हिस्सा लेती हैं। यह गलत है क्योंकि टेंडर का मतलब होता है अलग-अलग कंपनियां हिस्सा ले जिसके रेट से सरकार को ज्यादा फायदा हो, ठेका उसे मिले। लेकिन इसकी जगह अगर एक ही कंपनी की कई कंपनियां अलग-अलग नाम से टेंडर ले ले तो वह टेंडर संदिग्ध हो जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस समूह की एक कंपनी ने दो दिन पहले एक सेल कंपनी को अधिग्रहण कर लिया। और वह टेंडर में भाग लेने आ गई। सरिसा टोली टेंडर में कई प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। सीएजी ने इसके साथ साथ अन्य 10 खदानों के टेंडर को लेकर सवाल उठाये थे। सीएजी ने इलेक्ट्रानिक टेंडर की समीक्षा की थी और इसकी रिपोर्ट 2016 में संसद को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के लिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सभी पक्षों से जबाव मांगा मगर रिपोर्ट में लिखा है कि कोयला मंत्रालय सीएजी और गोयनका ग्रुप ने कोई जबाव नही दिया। सीएजी ने भी इशारा कर दिया इसके बाद भी काम चलता रहा। अब तो सुप्रीम कोर्ट के रदद किये जाने के बाद भी कथित तौर पर अडानी समूह की खदान को चलाए रखने के लिए नियमों में अपवाद पैदा करने की रिपोर्ट छप गई है। यहां कोयला मंत्रालय सीएजी की तरफ से कोई जवाब आएगा। अडानी ग्रुप द्वारा तो कहा है कि कोयला खदान का जो भी आवंटन हुआ है वह पारदर्शी तरीके से हुआ है। कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग प्रोसेस से हुआ है। अडानी समूह ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव से कहा कि इस प्रक्रिया से जुड़े सवाल संबंधित अथॉरिटी से पूछे जाएं। अडानी समूह और कोयला खदान को लेकर पहले भी खबर छप चुकी हैं। 2018 में पत्रिका ने समूह और कोयला खदान को लेकर कवर स्टोरी छापी थी। कवर पर 2.0 लिखा है। अडानी समूह ने इस पर कोई मानहानि नहीं की। इस पर केरवान ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए पत्रकार नीलिना से बातचीत की। नीलिना ने ही 2018 में कवर स्टोरी की थी। उम्मीद है पुरोन्जर ठाकुर के खिलाफ मानहानि का नोटिस वापस ले लिया जाएगा। वहीं 2018 में प्रकाशित इस खोजी रिपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट का एशियन कॉलेज आफ जर्नलिम अवॉर्ड मिला था। उसके बाद नीलिना ने अडानी के कामकाज पर और भी कई रिपोर्ट की। हमारा एक और मकसद है कि आम दर्शक दूसरे से बेहतरीन पत्रकारों के बारे में भी जाने जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जानने के लिए मेहनत कीजिए वरना आप को अंधेरे में रखकर कोई खजाना साफ करने की मेहनत में लगा मिलेगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी अडानी समूह पर लगे आरोपों का बिंदुवार जवाब दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सवाल है कि संसदीय सेबी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से छपी खबर में लिखा गया है कि सेबी इन आरोपों और अडानी के जवाबों का परीक्षण कर रही है। मगर अभी तक कोई अनियमितता सामने नहीं आई है। यह भी लिखा है कि सेबी अदानी समूह की कंपनियों के कारोबार और शेयर से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है। इस खबर में इस पर भी जोर दिया गया है कि सूत्रों ने कहा है कि सेबी के इस एक्शन को औपचारिक जांच नहीं समझना चाहिए। तो सेबी की जांच को औपचारिक मानेंगे तो फिर क्लीनचिट जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मामला दूसरे देशों में ऐसी कंपनियों का है, जिसके जरिए गुप्त रूप से लेन-देन हुआ है। उन कंपनियों का मालिक कौन है। उनका अदानी समूह के मालिक से क्या संबंध है। कंपनी से क्या संबंध है। ऐसे मामलों की जांच ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं ही कर सकती है। अगर आप जिसके सामने जीडीपी के आंकड़े देकर खुश होना चाहते हैं वह भी बता देते हैं दिसंबर की तिमाही में जीडीपी की दर 4.4 प्रतिशत रही। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट लगातार दो तिमाही में कम देखा गया है और उपभोक्ताओं की मांग में कमी देखी गई है। इसके बाद भी आप की चुप्पी और खुशी के जो भी कारण हैं। मगर देश की सच्चाई या सरकारी विकास के विज्ञापन के पोस्टरों को फाड़ देती। सीएमआईई की रिपोर्ट में लिखा गया है कि फरवरी महीने में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.45 प्रतिशत हो गई। मध्यप्रदेश में 03 साल से नर्सिंग की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मगर इस खबर की खबरों से गहरा संबंध है। नौजवान जब अपने करियर की बर्बादी पर चुप रह सकता है। अडानी की खबर से चुप रह सकता है। आज आप ही बता सकते हैं कि देश इस समय किस दिशा में जा रहा है और देश की दिशा और दशा बताने में हमारी मीडिया क्या भूमिका निभा रही है। देश के अंदर देशवासियों को वहीं बताया जा रहा है जो मोदी सरकार दिखाना चाहती है। यह देश के लिए लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है।

खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए हैं। जवाब नहीं है। अडानी समूह से पहले, नाथन एंडरसन द्वारा स्थापित हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म का पिछले छह वर्षो में 17 कंपनियों में धोखाधड़ी की ओर इशारा करने का ट्रैक रिकॉर्ड था।

मोदी और अडानी की इस जुगलबंदी के क्या मायने?

अडानी के प्राईवेट जेट में आराम फरमाते मोदी!

140 करोड़ की जनसंख्या के देश में एकमात्र भारतीय गौतम अडानी है जिसकी संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ी है। वह विश्व में एकमात्र आदमी होगा जिसे इतनी आर्थिक कलाबाजियां आती होंगी और इसी रहस्य को उजागर करने का काम हिंडनबर्ग ने बहुत ही बारीकि से किया है। गौतम अडानी ने अपने घोटालों को उजागर करने के काम को भारत के ऊपर हमला कहा है। इसे देखते हुए आज से 21 साल पहले का एक ऐसा ही तर्क याद आ रहा है। तब गुजरात दंगे की आलोचना करने वाले लोगों को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पांच करोड़ लोगों का अपमान करने वाला बताया था। अब वैसी ही दलील अडानी दे रहे हैं। 400 से अधिक पन्ने खर्च करके हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत के ऊपर हमला करार देते हैं। क्या इस जुमले से यह सच्चाई छिप जाएगी कि अडानी उद्योग समूह का विस्तार इतनी तेज रफ्तार से कैसे हुआ। वह भारत के ऊपर हमला जैसे जुमले का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जाहिर है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर परदा डालने के लिए, जिसमें यह बताया गया है कि अडानी ने कौन-कौन से फरेब किये हैं। गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं किया गया। और सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर जैसे कड़े शब्दों में आलोचना की थी। इस सबका गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास एक ही जवाब था कि पांच करोड़ गुजरातियों का अपमान किया जा रहा है।

इस देश के सामान्य नागरिकों के पसीने की कमाई से बैंक में जमा पूंजी को और जीवन बीमा जैसी कंपनी में करोड़ों देशवासियों की जिंदगी भर की कमाई के पैसे को लेकर अपनी खुद की पूंजी

सोशल मीडिया में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अडानी की दोस्ती से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं उसमें एक खबर चौंकाने वाली है। उस खबर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरह से अडानी और रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में सपोर्ट किया। बदले में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर बैठते ही पहले मुकेश अंबानी को पूरे देश में 4जी नेटवर्क और फिर गौतम अडानी को पूरा देश खरीदने की खुली छूट दे दी। प्रधानमंत्री ने अपने फायदे के लिए जिस तरह से गौतम अडानी के साथ सौदा किया है वह सौदा आज पूरे देश को महंगा पड़ गया है। अडानी ने विश्व स्तर

बढ़ाने में लगा हुआ अडानी देशभक्ति की आड़ में अपने घोटालों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और बात-बात में विरोधी दलों के नेताओं के घरों पर ईडी, आईबी की तरफ से द्वेषपूर्ण छापामारी का सिलसिला भी जारी है लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बाबत ये जांच एजेंसियां क्यों खामोश हैं? कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? इतने बड़े मामले में छापेमारी क्यों नहीं होती? बैंकों के सभी नियम-कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को, देश की आड़ में बोलते हुए देखकर, उसके औद्योगिक साम्राज्य के विस्तार का इतिहास देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान हुए बिना नहीं रह सकता।अडानी समूह का पिछले 30-35 सालों का सफरनामा देखा जाए तो मुंबई जैसे शहर में एक मामूली सी गहने की दुकान चलाने वाले अडानी आज भारत की आधे से भी अधिक बिजली का उत्पादन करने से लेकर कांडला जैसे पोर्ट के मालिक हैं। अडानी समूह की मालकियत होने का सफर और उस पोर्ट को कब्जे में करने के तुरंत बाद, मॅन्ग्रोव जैसे सैकडों हेक्टेयर जमीन पर सुरक्षित रखे गए अंतरराष्ट्रीय धरोहर को नष्ट करने का गुनाह कर चुके और उसके लिए ग्रीन ट्रायब्यूनल जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष रूप से बनाए गए कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस उद्योग समूह के लिए, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में सभी नियम-कानूनों की अनदेखी करते हुए, जबरदस्त पक्षपात किया है और इसी कारण गुजरात में ज्यादातर स्थानों पर अडानी ऊर्जा नाम के पेट्रोल पंपों से लेकर, और भी कई तरह के उद्योगों के लिए विशेष रूप से सहयोग किया है और अब तो संपूर्ण भारत में और कई अन्य देशों में भी अपने औद्योगिक साम्राज्य का विस्तार किया है। उसी सहयोग के बदले में नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 2013 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अडानी ने अपने प्रायवेट जेट विमान देकर मोदी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में मदद की है। तभी तो पांच सौ से अधिक चुनावी प्रचार सभा करने का भारत के चुनाव प्रचार के इतिहास में उन्होंने रेकॉर्ड बनाया और कितना पैसा दिया होगा सो अलग।

हम जरा इतिहास में जाते हैं तो आज से नब्बे साल पहले के जर्मनी में क्या हुआ था। हिटलर ने बाकायदा जर्मनी के सभी उद्योगपतियों की बैठक बुलाकर अपने दल को सत्ता में लाने के लिए अपनी पूंजी दिल खोलकर लगाने का आह्वान किया था और तत्कालीन जर्मनी के पूंजीपतियों ने हिटलर के इस आह्वान का साथ दिया था। 30 जनवरी 1930 को हिटलर जर्मनी के चांसलर पद पर आरूढ़ होने में कामयाब हुआ था और गिनकर पंद्रह साल नब्बे दिनों तक संपूर्ण यूरोप की छाती पर मूंग दलते हुए लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। एकछत्र राज करने के लिए हिटलर ने जर्मनी की सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया और गोएबल्स जैसे आदमी की मदद से उसने झूठ को लगातार फैलाने और झूठ को सच बनाने के लिए ए क

जबरदस्त प्रचारतंत्र खड़ा किया था। उस काले इतिहास को जिन्होंने अपनी आँखों से घटित होते देखा था उनमें कुछ लोग आज भी मौजूद हैं। वर्तमान भारत में भी कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश के लगभग सभी पूंजीपति वर्तमान सरकार को बनाने से लेकर उसे दोबारा सत्ता में वापसी कराने के लिए विशेष रूप से इकट्ठा होकर मदद करते रहे हैं। जिनमें गौतम अडानी नंबर एक पर हैं और इसीलिए इस उद्योग समूह की वृद्धि दर विश्व के औद्योगिक इतिहास में सबसे अधिक है। इसीलिए गौतम अडानी हिंडेनबर्ग रिपोर्ट को भारत के ऊपर हमला बताने की हिम्मत कर रहा है।

पर भारत की छवि को धूमिल कर दिया है जिसका नुकसान आर्थिक रूप से देश की जनता तो भुगत ही रही है, सामाजिक रूप से पूरा देश आने वाले कई वर्षो तक भुगतने को मजबूर हो गया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली में राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई तो उसमें वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की इच्छा व्यक्त की थी। वरिष्ठता के आधार पर अन्य नेताओं ने भी सहमति देने पर विचार किया था लेकिन नरेन्द्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना आरंभ

राष्ट्रवाद के चोले में फर्जीवाड़े को नहीं ढक सकते

गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने कहा है हिंडनबर्ग रिसर्च इस आरोप के जरिए भारत और उसकी कंपनियों की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। गौतम अडानी ने कहा था कि यह भारतीय कंपनियों की छवि बिगाड़ने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने 106 पेज की एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें अडानी ग्रुप पर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में स्टॉक मैनिपुलेशन और एकाउंटिंग फ्रॉड किया गया है। इसके साथ ही टैक्स हैवन वाले देशों का अवैध इस्तेमाल कर पर्सनल संपत्ति बनाने में मदद हासिल की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने 413 पेज का जवाब भेजा था। इस पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग का जवाब आया। उसका कहना है कि राष्ट्रवाद को चोला ओढ़कर धोखाधड़ी करने को सही नहीं ठहरा सकते। अडानी ग्रुप ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत आरोपों का जवाब देने की जगह अडानी ग्रुप राष्ट्रवाद का सहारा ले रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, हम मानते हैं कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोसी है और एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। इसके साथ ही हम यह भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह ग्रुप राष्ट्रवाद की आड़ में देश को लूट रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, हमारा मानना है कि फ्रॉड किसी के द्वारा भी किया जाए वह फ्रॉड ही होता है, आप इसे देश पर हमला बताकर बच नहीं सकते। उसने कहा कि उसने अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे थे जिसमें से अडानी ने 62 सवालों के जवाब नहीं दिए। इनमें से कई सवाल कारोबारी लेन-देन की प्रवृत्ति और हितों के टकराव के बारे में पूछे गए थे। गौतम अडानी ग्रुप ने इनका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें काफी हद तक हमारी रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अडानी साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए रिपोर्ट का टाइटल ही काफी था। कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है? निश्चित ही अडानी समूह 24 जनवरी के दिन को काला दिवस के रूप में ही याद करेगा। रिपोर्ट दावा करती है कि अगर आप हमारी जांच के निष्कर्षो को नजरअंदाज भी करें और सिर्फ अडानी समूह के वित्तीयों को अंकित मूल्य पर लेते हैं, तो इसकी 07 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों के गगनचुंबी मूल्यांकन की हवा इस कदर निकल जाती है।

कर दिया। काफी खींचतान और अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुलझा और यह तय हुआ कि जो भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी फंड एकत्रित करेगा पार्टी उसे ही प्रधानमंत्री पद का

हिंडनबर्ग रिपोर्ट: एक नज़र में

Hindenburg Research Report say about Adani?

Hindenburg Research, a well-known short seller in the United States, disclosed short positions in the Adani Group on Wednesday, accusing the conglomerate of the improperly broad use of companies based in offshore tax havens and raising concerns about excessive debt levels.

What the Hindenburg report says

The firm published a research paper titled 'Adani Group: How the World's Third Richest Man Is Pulling the Biggest Scam in Corporate History' and revealed the findings of its two-year investigation presenting evidence that the Adani group, valued at Rs 17.8 trillion, it has engaged in a brazen scheme of stock manipulation and accounting fraud for decades.

According to the report, Gautam Adani, the founder and chairman of the Adani Group, has a net worth of about $120 billion, which has increased by more than $100 billion in the past three years, mainly as a result of the growth in the price of actions in the group top seven publicly traded companies, which have risen by an average of 819 per cent during that time.

Hindenburg says it identified 38 alleged Mauritius-based shell companies "controlled by" Vinod Adani, Gautam Adani's older brother, along with several other similar companies based in Cyprus, the United Arab Emirates, Singapore and various Caribbean islands.

The alleged scheme involved the use of offshore shell entities to generate artificial turnover. Rajesh was arrested at least twice over separate allegations of forgery and tax fraud. He was subsequently promoted to serve as Managing Director of Adani Group. (11/x) https://t.co/RT1sJqlKoZ

Stock manipulation and money laundering

The report alleges that the shell companies are used for "stock manipulation" and "money laundering", using the private companies of the Adani Group on the books of publicly traded companies "to maintain the appearance of solvency and health financial".

The report also criticizes "investors, journalists, citizens, and even politicians," saying they held back on "big blatant fraud [taking place] in broad daylight" for fear of retaliation. As of Wednesday morning Later, the Hindenburg report received little coverage in the Indian media outside of syndicated reports from business news agencies such as Reuters or Bloomberg.

Hindenburg Research said the Adani Group companies are intricately and clearly linked and dependent on one another. None of the listed entities is isolated from the performance, or failure, of the other companies in the group. "We believe that it could take a single severe liquidity event in a single entity to trigger a negative cascade of events in other entities in the group that could affect the entire Adani Group."

Adani companies under liquidity risk

Four of Adani's publicly traded companies are near the delisting threshold due to high developer ownership, according to a report published by Hindenburg Research, an investment research firm that focuses on sales in short activists.

The report also said that five companies in the group (all but Adani Ports and Adani Wilmar) have current ratios below 1.0, suggesting increased near-term liquidity risk. Furthermore, Adani Wilmar, a new company with current insider ownership of 87.94%, must reduce its insider holdings to 75% by early 2025 to meet these requirements – a significant feat requiring the offloading of 12.94% of its current insider equity.

Listed companies in India are subject to regulations requiring all promoter holdings to be disclosed. The rules also require publicly traded companies to have at least 25 per cent of the free float held by non-promoters to mitigate manipulation and insider trading.

Adani Enterprises, Adani Transmission, Adani Power and Adani Total Gas report that more than 72 per cent of their shares are held by insiders. In addition, Adani Wilmar, a new company with a current 87.94 per cent insider ownership, must reduce its insider holdings to 75 per cent.

The report says that for many Adani-listed companies, a large portion of their "public" shareholders are funds based in the opaque jurisdiction of Mauritius. "Importantly, the funds identified in this section, which we believe should be classified as 'promoting' (internal) entities, hold enough shares of Adani-listed companies to put four of them well above the 75% threshold, which causes delisting.

An offshore network

While many of the allegations made by Hindenburg against Adani had already surfaced, including overvaluations and concentrated holdings of Mauritian-based investors in his companies, some details collected from across the Mauritian registry have been made public for the first time, according to Brian Freitas an Auckland-based analyst who publishes independent research on the Smartkarma website.

Hindenburg said he had taken a short position in Adani's companies through US-traded bonds and non-Indian-traded derivatives. **Here is a quick summary of some of the main accusations made by him.**

- 1. 38 Mauritian shell entities controlled by Adani's brother Vinod Adani or his close associates were identified, as well as entities controlled by him in other tax havens.
- 2. The fictitious offshore network appears to be used for profit manipulation.
- 3. Adani Group has previously been the focus of four major government investigations related to fraud allegations.
- 4. Adani Enterprises and Adani Total Gas appear to be audited by a small company, with no current website, only four partners and 11 employees and have only audited one other publicly traded company.
- 5. The auditor "hardly seems capable of complex audit work" when Adani Enterprises alone has 156 subsidiaries and many more joint ventures.

Bull Run Slowdown

Adani's companies trade at a price-earnings ratio many times that of similar companies both in India and around the world, including companies in the Reliance empire of rival tycoon Mukesh Ambani, Adani's predecessor as the world's richest man from Asia. There are some signs that the bull run is slowing, with most shares in the Adani group starting the year lower even before the Hindenburg report.

Investors and analysts have also raised concerns about the high debt levels seen in the empire's listed units. The gross debt of six Adani companies (Adani Enterprises, Adani Green Energy, Adani Ports, Adani Power, Adani Total Gas and Adani Transmission) stood at Rs 1.88 trillion ($23 billion) at the end of March 2022.

Hindenburg Research Adani Report

- Today we reveal the findings of our 2-year investigation, presenting evidence that the INR 17.8 trillion (U.S. $218 billion) Indian conglomerate Adani Group has engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades.
- Gautam Adani, Founder and Chairman of the Adani Group, has amassed a net worth of roughly $120 billion, adding over $100 billion in the past 3 years largely through stock price appreciation in the group's 7 key listed companies, which have spiked an average of 819% in that period.
- Our research involved speaking with dozens of individuals, including former senior executives of the Adani Group, reviewing thousands of documents, and conducting diligence site visits in almost half a dozen countries.
- Even if you ignore the findings of our investigation and take the financials of Adani Group at face value, its 7 key listed companies have 85% downside purely on a fundamental basis owing to sky-high valuations.
- Key listed Adani companies have also taken on substantial debt, including pledging shares of their inflated stock for loans, putting the entire group on precarious financial footing. 5 of 7 key listed companies have reported 'current ratios' below 1, indicating near-term liquidity pressure.
- The group's very top ranks and 8 of 22 key leaders are Adani family members, a dynamic that places control of the group's financials and key decisions in the hands of a few. A former executive described the Adani Group as "a family business."
- The Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated U.S. $17 billion. Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax-haven jurisdictions like Mauritius, the UAE, and Caribbean Islands, generating forged import/export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies.
- Gautam Adani's younger brother, Rajesh Adani, was accused by the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) of playing a central role in a diamond trading import/export scheme around 2004-2005. The alleged scheme involved the use of offshore shell entities to generate artificial turnover. Rajesh was arrested at least twice over

उम्मीदवार बनायेगी। पार्टी पदाधिकारियों की यह बात सुनकर तुरंत नरेन्द्र मोदी ने अपना गुजराती दिमाग लगाया और तुरंत गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से चर्चा कर उन्हें पार्टी फंड जुटाने के लिए राजी कर लिया। उस समय तक पार्टी और देश की

एलआईसी को लगा 50 हजार करोड़ का चूना

एलआईसी को अडानी समूह में किए गए अपने निवेश पर 49,728 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने गणना करके बताया है कि जीवन बीमा निगम अडानी का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है और उसे बीते 50 दिनों में भारी झटका लगा है। जब 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके बाद अडानी के शेयरों की कीमत अब तक 80 प्रतिशत गिर चुकी है। दरअसल, एलआईसी ने अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में भारी पैसा लगाया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, 31 दिसंबर 2022 तक अडानी ग्रुप की इन सातों कंपनियों में एलआईसी के निवेश का बाजार मूल्य 82,970 करोड़ रुपये था, जो 22 फरवरी 2023 को 33,242 करोड़ रुपये रह गया। यानी एलआईसी के बाजार मूल्य में करीब 50,000 करोड़ रुपये की कमी आयी। ये आंकड़े 31 दिसंबर 2022 तक अडानी के शेयरों के बाजार मूल्य और वर्तमान बाजार मूल्य के अंतर पर आधारित हैं। इससे पहले 30 जनवरी को एलआईसी ने बाजार नियामक सेबी को बताया था कि उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों के 30,127 करोड़ के शेयर खरीदे थे, जिनकी कीमत 27 जनवरी तक 56,142 करोड़ रुपये थी। एलआईसी ने ये भी बताया कि 30 जनवरी तक उसने अडानी की कंपनियों में कुल 36,474 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसका मतलब ये है कि जब अडानी के शेयर बेतहाशा नीचे गिर रहे थे। एलआईसी कंपनी ने 28-30 जनवरी के बीच करीब 6,347 करोड़ रुपये और लगाए थे। एलआईसी में आम गरीब और मजदूर और मेहनतकश लोगों के जीवनबीमा के पैसे लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी की जनता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी के साथ मिलकर क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मोदी ने अंबानी और अडानी के कंधे पर बंदूक रखकर टिगर दबाया और प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने तुरंत नि-शुल्क 4जी स्पेक्ट्रम मुकेश अंबानी समूह को उपलब्ध करवा दिया। ऐसा ही गौतम अडानी के साथ हुआ।

नजदीकी की वजह से इस सरकारी कंपनी ने अडानी की कंपनियों में निवेश किया था। एलआईसी को लगे इस झटके के बाद सोशल मीडिया पर अडानी पर जेपीसी जाँच की मांग तेज हो गयी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खरगे ने लिखा है कि एलआईसी को हुए इतने बड़े नुकसान

के बाद एलआईसी के 29 करोड़ पालिसी धारकों और लाखों खुदरा निवेशकों के करीब 50,000 करोड़ डूब गए हैं।

अडानी समूह में एलआईसी का निवेश नकारात्मक स्थिति में पहुंचा

23 फरवरी तक अडानी समूह के शेयर की कीमतों में गिरावट यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी कि भारत का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का निवेश अडानी की कंपनियों में नकारात्मक हो गया है। अडानी कंपनियों में एलआईसी होल्डिंग की निधि 500 करोड़ रुपये और घट गई है। 22 फरवरी तक एलआईसी अडानी समूह के अपने निवेश में 94 करोड़ रुपये के लाभ में था, लेकिन अगले दिन वह 500 करोड़ रुपये के घाटे में चला गया। अडानी स्टॉक में हालिया बिकवाली के बीच एलआईसी को 49,728 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। इसमें कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में एलआईसी के निवेश का बाजार मूल्य 23 फरवरी 2023 को करीब 33,242 करोड़ रुपये गिर गया, यह 30 दिसंबर 2022 को करीब 82,970 करोड़ रुपये था।

एसबीआई को भी भारी झटका

भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अदानी समूह की कंपनियों को 27 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। गौतम अडानी को लगे झटके का असर एसबीआई के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। गौतम अडानी की कंपनियों को एसबीआई ने बारी भरकम कर्ज दिया है। अगर कंपनी ये कर्ज नहीं चुका पाती है तो बैंक को बड़ा नुकसान होगा। इस डर से एसबीआई के निवेशक भी शेयर बेचकर निकल रहे हैं। 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो एसबीआई के शेयर 604.60 रुपये पर बंद हुआ था। 23 फरवरी को कंपनी के शेयर गिरकर 521 रुपये पर पहुंच गए। एक महीने में एसबीआई के शेयर 14 फीसदी तक टूट गए। यानी देखा जाए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आंच सिर्फ अडानी तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि उनसे जुड़े लोगों को भी इसका नुकसान हो रहा है।

विश्व में 609 नंबर पर अमीरों की सूची में शामिल गौतम अडानी 08 वर्ष के अंदर 02 नंबर पर कैसे पहुंचे यह हर कोई जानने को बेताब था।

भाजपा नेताओं ने साधी चुप्पी- गौतम अडानी का अरबों रूपये का भ्रष्टाचार सामने के बाद तमाम भाजपा नेता पूरी तरह से चुप्पी साधकर बैठ गये हैं। संबित पात्रा, रविशंकर सहित कई वरिष्ठ

नेता गौतम अडानी के भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी शीर्षस्थ ने यह निर्देश जारी किये हैं कि जो भी भाजपा नेता इस पूरे मामले पर बयानबाजी करेगा उसका टिकट आगामी चुनाव में कट सकता है। यही कारण है कि सभी मौन धारण किये हुए बैठे हैं।

बीजेपी नेताओं का कालाधन लगा है अडानी की कंपनी में- रिपोर्ट के अनुसार

अडानी का पहले भी रहा है विवादों से नाता

हाल में गौतम अडानी ने अपनी पब्लिक इमेज को बिल्ड करने के लिए कई घरेलू और विदेशी मीडिया हाउस को बड़े-बड़े इंटरव्यू दिए। इतना ही नहीं मीडिया में दखल बढ़ाने के लिए एनडीटीवी जैसी बड़ी डील की है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पैदा हुआ संकट गौतम अडानी के लिए अग्निपरीक्षा इसलिए भी है क्योंकि इसने ना सिर्फ उनकी कंपनियों के शेयर्स का कुल एमकैप 4.8 अरब डॉलर तक कम किया है, बल्कि ये उनकी निजी छवि को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गौतम अडानी का नाम विवाद में पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर तो वह हमेशा ही विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। इससे पहले केरल में 90 करोड़ डॉलर के निवेश वाली एक बंदरगाह परियोजना के निर्माण को लेकर मछुआरों के साथ उनके समूह का विवाद हुआ ही था, जिसमें उन्होंने मछुआरों के लीडर्स और राज्य सरकार पर केस कर दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कार्माइकल कोयला खान प्रोजेक्ट के लिए उनके समूह को कई साल तक पर्यावरण एक्टिविस्ट का विरोध झेलना पड़ा। हाल में जब उन्होंने अंबुजा और एसीसी सीमेंट का अधिग्रहण किया तो नई कंपनी अडानी सीमेंट को हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कंपनी को अपने प्लांट में उत्पादन बंद करना पड़ा है।

भाजपा नेताओं के पास जो कालाधन था उसे गौतम अडानी ने विदेशों में अपनी फर्जी कंपनियां बनाकर व्हाइट करने का कार्य किया है। लेकिन अडानी और भाजपा नेताओं के इस मंसूबे पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पानी फेर दिया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत का वर्षो से भ्रष्टाचार कर जमा किये गये इन

व्यापार बढ़ाने जनता के करोड़ों रुपए डुबाए, अब भागने की तैयारी में

अडानी

रूपयों की रिकवरी कैसे होगी। होगी भी या नहीं। यही सवाल देश के आमजन के दिमाग भी चल रहा है कि अडानी ने एसबीआई और एलआईसी का जो अरबों रूपये का पैसा लिया है अगर वो उसे चुकाने में असमर्थ रहा तो यह दोनों ही संस्थान पूरी तरह से डूब जायेंगे, जिसके बाद देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे

मोदी राज के शुरूआती साल में हुई तीन लाख करोड़ के लोन माफ

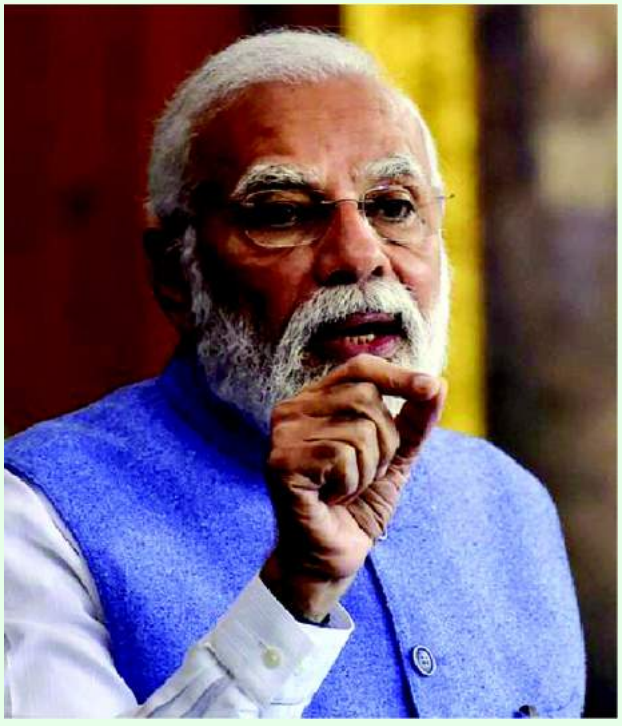

मोदी सरकार के शुरूआती चार सालों में 21 सरकारी बैंको ने 03 लाख 16 हज़ार करोड़ के लोन माफ़ किए हैं। यानी अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच तीन लाख करोड़ रुपये के लोन माफ किए गए हैं? यह भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के कुल बजट का दोगुना है। सख़्त और ईमानदार होने का दावा करने वाली मोदी सरकार में तो लोन वसूली ज्यादा होनी चाहिए थी, मगर हुआ उल्टा। एक तरफ एनपीए बढ़ता गया और दूसरी तरफ लोन वसूली घटती गई। यही नहीं इस दौरान बैंकों को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से हज़ारों करोड़ रुपये बैंकों में डाले हैं, जिस पैसे का इस्तेमाल नौकरी देने में खर्च होता, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देने में खर्च होता वो पैसा चंद उद्योगपतियों पर लुटा दिया गया। 2018-19 में इन तीनों मद के लिए बजट में 1 लाख 38 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अगर लोन वसूल कर ये पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर ख़र्च होता तो समाज पहले से कितना बेहतर होता। अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच बैंकों ने मात्र 44,900 करोड़ रुपये की वसूली की है। बाकी सब माफ। इसे अंग्रेज़ी में राइट ऑफ कहते हैं। ये आंकड़ा भारतीय रिज़र्व बैंक का है। जबकि भाजपा ने अप्रैल महीने में ट्वीट किया था कि 2016 में इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के कारण 04 लाख करोड़ रुपये लोन की वसूली की गई है। रिज़र्व बैंक का डेटा कहता है कि 44,900 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। गनीमत है कि इस तरह की खबरें हिन्दी के अखबारों में नहीं छापी जाती हैं इसलिए जनता का एक बड़ा हिस्सा इन अखबारों के ज़रिए बेवकूफ बन रहा है। मोदी सरकार के मंत्री एनपीए के सवाल पर विस्तार से नहीं बताते हैं। बस इस पर ज़ोर देकर निकल जाते हैं कि ये लोन यूपीए के समय के हैं। जबकि वो भी साफ-साफ नहीं बताते कि 07 लाख करोड़ के एनपीए में से यूपीए के समय का कितना हिस्सा है और मोदी राज के समय का कितना हिस्सा है। क्या हमारा आपका लोन माफ होता है? फिर इन उद्योगपतियों का लोन कैसे माफ हो जाता है? पांच साल से उद्योगपति चुप हैं। वे कुछ नहीं बोलते हैं। नोटबंदी के समय भी नहीं बोले। उद्योगपति चुप इसलिए कि उनके हज़ारों लाखों करोड़ के लोन माफ हुए हैं? तभी वे जब भी बोलते हैं, मोदी सरकार की तारीफ़ करते हैं। कायदे से मोदी राज में तो लोन वसूली ज्यादा होनी चाहिए

भी डूब जायेंगे।

अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए सवा महीना पूरा हो गया है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की कंपनियों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। तबसे कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से अडानी की कंपनियों का मार्केट कैप 12 लाख गिर चुका है। इसका असर गौतम अडानी की संपत्ति पर

थी। वो तो सख़्त और ईमानदार होने का दावा करती है। मगर हुआ उल्टा। एक तरफ एनपीए बढ़ता गया और दूसरी तरफ लोन वसूली घटती गई। 21 सरकारी बैंकों ने संसद की स्थायी समिति को जो डेटा सौंपा है उसके अनुसार इनकी लोन रिकवरी रेट बहुत कम है, जितना लोन दिया है उसका मात्र 14.2 प्रतिशत लोन ही रिकवर यानी वसूल हो पाता है। मोदी राज में एनपीए कैसे और किस तेज़ी से बढ़ रहा है। 2014-15 में एनपीए 4.62 प्रतिशत था जो 2015-16 में बढ़कर 7.79 प्रतिशत हो गया। दिसंबर 2017 में एनपीए 10.41 प्रतिशत हो गया। यानी 07 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये। इस राशि का मात्र 1.75 लाख करोड़ रुपये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गया है। यह जून 2017 तक का हिसाब है। उसके बाद 90,000 करोड़ रुपये का एनपीए भी इस पंचाट में गया। यहां का खेल भी हम और आप साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे।

निजीकरण की वकालत करने वाली ये प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट बैंकों से लोन क्यों नहीं लेती हैं? सरकारी बैंकों को क्या लूट का खजाना समझती हैं? क्या आप जानते हैं कि करीब 08 लाख करोड़ रुपये का एनपीए कितने उद्योगपतियों या बिजनेस घरानों का है? गिनती के सौ भी नहीं होंगे। तो इतने कम लोगों के हाथ में 03 लाख करोड़ रुपये जब जाएगा तो अमीर और अमीर होंगे कि नहीं। जनता का पैसा अगर जनता में बंटता तो जनता अमीर होती।

भी हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, अमीरों की सूची में गौतम अडानी 2 नंबर से फिसलकर 29वें नंबर पर पहुंच गए है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सबकुछ ठीकठाक नहीं है। ग्रुप दशकों से खुल्लम-खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है।

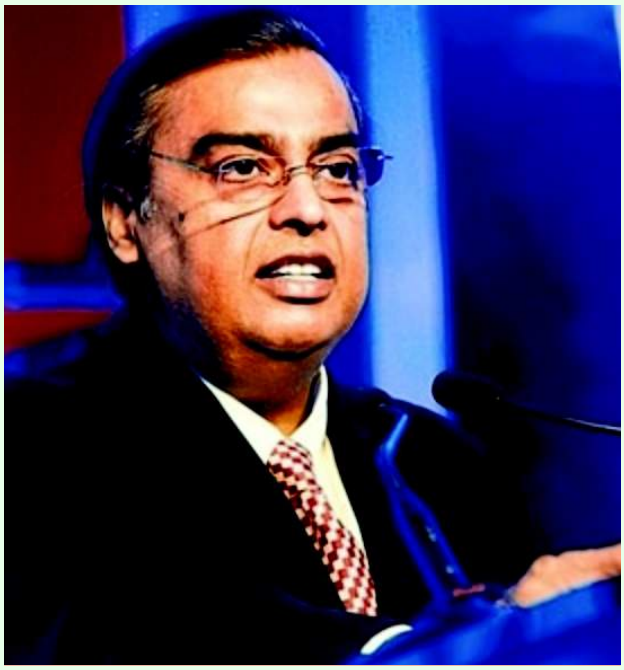

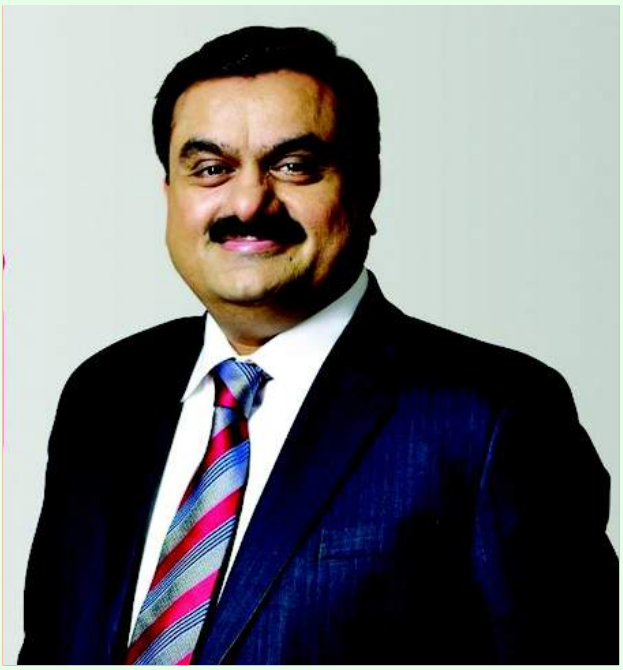

मोदी ने अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्ज माफ़ किये?

कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी चुनावी रैलियों में दावा करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 शीर्ष उद्योगपतियों के बैंक ऋण माफ़ किए हैं। राहुल गांधी के अनुसार इस क़र्ज़ की राशि 3.5 लाख करोड़ रुपये है, जो एक उत्तरप्रदेश जैसे एक बड़े राज्य के एक साल के बजट के बराबर है। यह दावा करके राहुल गांधी यह बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे अमीर लोगों के मित्र हैं। वो पहले ही मोदी सरकार को सूट-बूट की सरकार बता चुके हैं। सरकारी बैंकों के क़र्ज़दार अधिकतर बड़े उद्योगपति और बड़ी कंपनियां ही हैं। इसलिए डिफॉल्टर्स में उनके नाम ऊपर हैं। इसलिए जब भी क़र्ज़ माफ़ किये जाएंगे तो बड़े उद्योगपतियों की संख्या अधिक होगी। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 3.5 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ माफ़ किया। एक सरकारी बयान के मुताबिक़ 2000 से अधिक उद्योगपति और कंपनियां बैंकों का 3.88 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ नहीं चुका सकीं। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सार्वजनिक रैलियों में ऐसा दावा किया है। उन्होंने हाल में कई बार ऐसा किया। सबसे पहले दिसंबर 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनावी संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने पिछले साल के अंत में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान रैलियों में इस दावे को दोहराया। मोदी सरकार ने राज्यसभा को बताया था कि सरकारी बैंकों ने अप्रैल 2014 और सितंबर 2017 के बीच 2.41 लाख करोड़ रुपये के नॉन परफार्मिंग एसेट को खाते से बाहर किया था। यह राशि 2018 के अंत तक 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर 88 सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है? उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप है। हिंडनबर्ग ने पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का

ढ़ाई लाख करोड़ के कर्जे में है अडानी समूह

गौतम अडानी ने अपनी कंपनियों को स्थापित करने के लिए पिछले सात वर्षो में सरकार से अरबों रुपये का कर्जा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के ऊपर आज के समय में ढ़ाई लाख करोड़ रुपये का कर्जा है। यह कर्जा उन्होंने कई बैंकों और एलआईसी से लिया है। केंद्र सरकार के दबाव में आकर एलआईसी और एसबीआई ने मजबूरी में आकर गौतम अडानी की कंपनियों के तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के शेयर खरीदे। जबकि मोदी सरकार ने इससे पहले ही गौतम अडानी के ऊपर 74 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया और दूसरी तरफ इस कर्जे की भरपाई के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव को सातवें आसमान पर पहुंचाया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमोटर्स ने शेयरों को गिरवी रखकर उधार लिया है, अदानी ग्रुप पर कर्ज़ का भारी बोझ बड़ी समस्या है। निवेशक और विश्लेषक पहले भी अदानी समूह की शेयर बाज़ार में लिस्टेड कंपनियों पर कर्ज़ के बोझ को लेकर चिंता ज़ाहिर कर चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक मार्च 2022 के अंत तक अदानी समूह की छह कंपनियों अदानी इंटरप्राइसेज़, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन पर 1.88 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ था। आंकड़े भी बताते हैं कि अदानी ग्रुप की सात सूचीबद्ध कंपनियों पर कर्ज़ उनके इक्विटी से यादा है। अदानी ग्रीन एनर्जी पर तो इक्विटी से दो हज़ार प्रतिशत यादा कर्ज़ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी ग्रुप की भारतीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध सात कंपनियों के शेयरों की कीमत इसी सेक्टर की प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले बहुत अधिक मूल्य पर हैं और इनका वैल्यूएशन 85 प्रतिशत से अधिक है। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में कहता है, अगर आप हमारी जाँच रिपोर्ट को नकार भी दें और अदानी समूह के वित्तीय लेखा-जोखा का बारीक विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि इसकी सात लिस्टेड कंपनियों में 85 पर्सेंट तक की गिरावट की संभावना है और वजह साफ़ है कि शेयरों का वैल्यूएशन आसमान की ऊँचाई पर है। फिच समूह की फर्म क्रेडिटसाइट्स ने पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के भारी कर्ज में डूबे होने की बात कही थी। उसका कहना था कि अडानी ग्रुप बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर उस राशि का इस्तेमाल अपने मौजूदा कारोबार के विस्तार एवं नए कारोबारों को खड़ा करने में कर रहा है। क्रेडिटसाइट्स ने यह आशंका भी जताई थी कि हालात बिगड़ने पर समूह की ऋण-समर्थित कारोबार योजनाएं भारी कर्ज के जाल मे डूब सकती हैं और इसका नतीजा एक या अधिक कंपनियों के कर्ज भुगतान चूक के रूप में भी आ सकता है।

नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एक्जक्यूटिव डॉयेरक्टर क्यों बनाया गया है? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब अब तक अदानी ग्रुप ने नहीं दिया है।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से क्या निवेशकों को घबराना चाहिए?

बाज़ार विश्लेषक मानते हैं कि इस रिसर्च रिपोर्ट का असर अदानी समूह के शेयरों के अलावा बाज़ार पर भी दिखा है। रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं, लोग उनके जवाब अदानी समूह के बजाय सेबी से जानना चाहते हैं। शेयर एनालिस्ट आसिफ़ इकबाल का कहना है कि इस तरह की रिपोर्ट छोटी अवधि में काफ़ी नुक़सान पहुँचाती है। आसिफ़ कहते हैं, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मज़बूत हैं और अदानी समूह इन आरोपों का सही से जवाब देता है

प्रमुख सेक्टर्स में अडानी ने फैलाया साम्राज्य

सवा महीन पहले गौतम अडानी भारत के ही नहीं एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। कामयाबी की नई इबारत लिखते हुए दुनिया के तीसरे धनी व्यक्ति थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 30 मार्च 2014 को गौतम अडानी के पास केवल 5.10 अरब डॉलर की संपत्ति थी। 19 जून 2021 तक आते-आते उनकी संपत्ति कई गुना उछल कर 76.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इसके बाद तो उनकी दौलत को पंख लग गए। 29 अप्रैल 2022 को उन्होंने 122 अरब डॉलर का मुकाम हासिल कर लिया और 137 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी 8 साल में अडानी की दौलत में 27 गुना से अधिक हुआ है। अब सवाल उठता है कि अडानी के पास अचानक से इतनी संपत्ति कहां से आ गई। तो इसका एक ही जवाब है शेयर बाज़ार में तेजी से। गौतम अडानी ने 1988 से अपना बिजनेस शुरू किया था। अभी उनकी 07 कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं। अडानी प्राइवेट सेक्टर में देश का सबसे बड़ा पोर्ट चलाते हैं। उन्होंने 06 एयरपोर्ट सरकार से खरीदे हैं। मुंबई एयरपोर्ट अब उनका है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करते हैं। वहीं, बिजली में लगने वाला कोयले का सबसे ज्यादा खनन करते हैं। देश में सबसे ज्यादा सीमेंट बनाते हैं। फार्च्यून ब्रांड से तेल, आटा, चावल, बेसन जैसी चीजें भी बेचते हैं। उनकी कंपनियों के शेयरों की कीमत राकेट की तरह भाग रही थी। इनका मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपये से

तो निवेशकों का घाटा थम सकता है। लेकिन एक बात तय है अदानी समूह जितना बड़ा है और जितना उस पर कर्ज़ का बोझ है इसकी आँच कुछ बैंकों पर भी पड़नी तय है। बाज़ार विश्लेषक अरुण केजरीवाल कहते हैं, जहाँ तक इस रिपोर्ट के असर की बात है तो अडानी इंटरप्राइसेज़ के एफ़पीओ पर तो इसका असर होना तय है और क्योंकि कंपनी ये एफ़पीओ बैंकों का

ज्यादा था। इन्हीं कंपनियों में शेयर होने के चलते अडानी की संपत्ति बढ़ी। उनकी कंपनियों के साल 2022 के परफार्मेंस की बात करें तो अडानी पावर 292 फीसद उछला। अडानी इंटरप्राइजेज की इस साल अब तक की उछाल 294 फीसद है। अडानी पोर्ट्स 108 तो अडानी ग्रीन करीब 80 फीसद का रिटर्न दिया है। जबकि, अडानी विल्मर की उछाल इस अवधि में 158 फीसद से अधिक रही। अडानी टोटल ऐस ने भी इस दौरान 109 फीसद तो अडानी ट्रांसमिशन ने 127 फीसद की उड़ान भरी।

अडानी ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षो में ही अपने कारोबार का बड़ी तेजी से विस्तार किया है। कोयला खनन, बंदरगाह, हवाईअड्डा, डेटा सेंटर, सीमेंट, एल्युमिनियम और शहरी गैस वितरण जैसे तमाम कारोबार क्षेत्रों में समूह काम कर रहा है।

अडानी की संपत्ति में आई भारी गिरावट- दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर उनकी संपत्ति 125 अरब डॉलर से पार जा चुकी थी। हिंडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने इसमें ऐसा डेंट मारा है कि 24 घंटे के भीतर उनकी संपत्ति में करीब 21 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई। मौजूदा वक्त में उनकी संपत्ति 35 अरब डॉलर पर आ गई है। जनवरी के 29 दिन में उनकी संपत्ति में सीधे 27.9 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। अब वह दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति रह गए हैं। इस रिपोर्ट ने एक झटके में उन्हें जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वारेन बफेट और लैरी एलिसन से पीछे कर दिया है।

तीन साल में 1500 प्रतिशत तक का रिटर्न- अडानी समूह की शेयर बाजार में 07 कंपनियां लिस्ट हैं। खबर के मुताबिक इस संकट से पहले के तीन साल को देखें तो उनकी कुछ कंपनियों के शेयर का रिटर्न 1500 प्रतिशत तक रहा है। इसकी वजह उन्होंने अपने कारोबार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, साथ ही इसे अलग-अलग सेक्टर तक फैलाया है। हालांकि इसके पीछे बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती को एक वजह मानते हैं। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी दोनों ही गुजरात राज्य से आते हैं।

धरती, अग्नि, जल, आकाश...सब कुछ अडानी के पास- अडानी ग्रुप के कारोबार को देखें तो ये धरती, अग्नि, जल और आकाश यानी लगभग हर सेक्टर में मौजूद है। अडानी ग्रुप जहां

माइनिंग सेक्टर (धरती) में काम करता है। वहीं सोलर एनर्जी (अग्नि) में उसका व्यापक कारोबार है। इसके अलावा अडानी समूह एयरपोर्ट ऑपरेशन (आकाश) संभालने वाली अब देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं हाल में कंपनी ने वाटर प्यूरिफिकेशन से लेकर डिस्ट्रिब्यूशन (जल) के बिजनेस में उतरने की बात कही है। जबकि समूह की अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी बंदरगाह ऑपरेटर कंपनी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप फॉर्च्यून ब्रांड के साथ एफएमसीजी, बिजली वितरण, गैस वितरण, मीडिया, सीमेंट और रीयल्टी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी काम करता है।

कुछ कर्ज़ उतारने के लिए लाई है, इसलिए इसके नाकाम होने की स्थिति में कुछ बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर इसका असर पड़ेगा ही। एयूएम कैपिटल के रिसर्च प्रमुख राजेश अग्रवाल मानते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट में कुछ आरोप बेहद गंभीर हैं। राजेश कहते हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट का असर अदानी समूह की कंपनियों पर लंबे समय तक रहेगा।

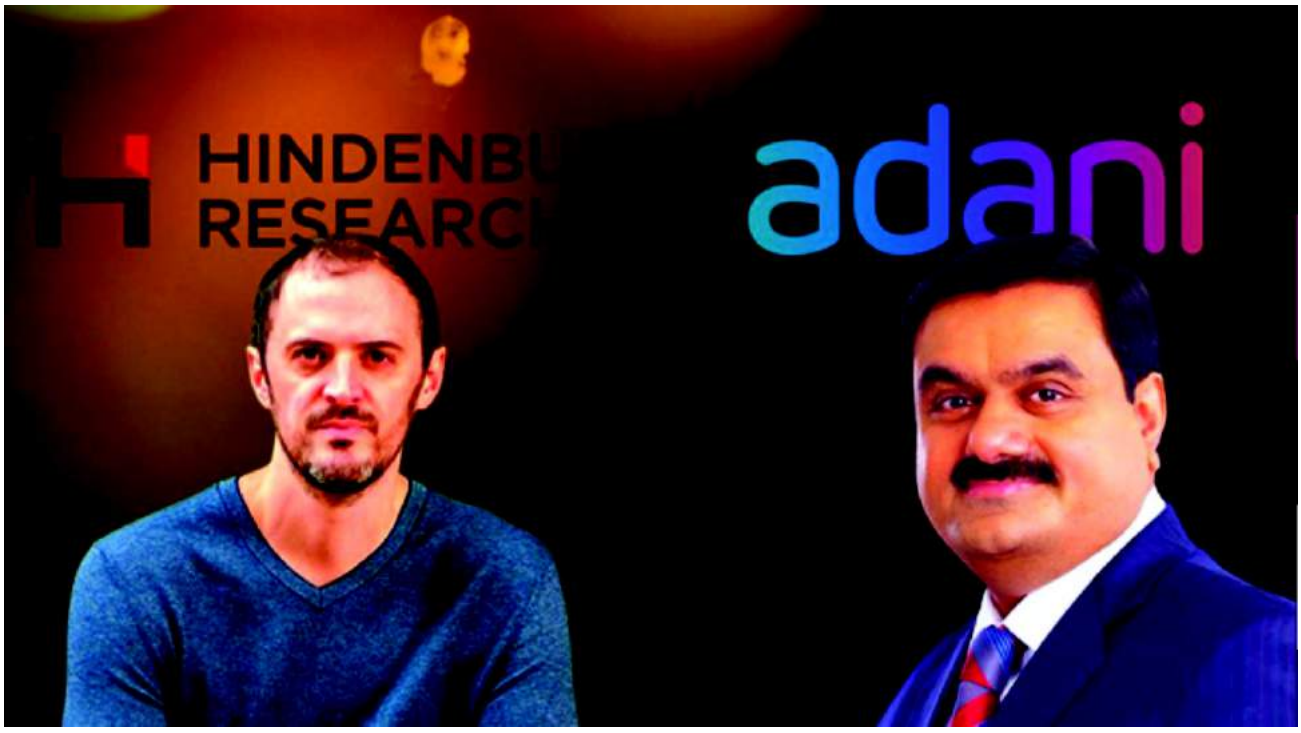

यह है हिंडनबर्ग कंपनी के मालिक नाथन एंडरसन। इनकी ही एक रिपोर्ट से भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी का पूरा साम्राज्य हिल गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इतिहास रहा है, इनकी रिपोर्ट से विश्व भर में तहलका मच जाता है।

विदेशी निवेशक इससे प्रभावित ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ख़ुद की रिसर्च टीम होती है, तो वो निवेश करने या शेयर बेचने का फ़ैसला इस तरह की रिपोर्ट के आधार पर कम ही लेते हैं। राजेश कहते हैं, शेयरों की कीमतों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ अदानी समूहों के शेयरों के साथ नहीं है। इस रिपोर्ट से निश्चित तौर पर निवेशकों का सेंटिमेंट प्रभावित हुआ है और यही वजह है कि अदानी समूह के अलावा बैंकिंग और आईटी शेयरों में भी बिकवाली हुई है। अमेरिकी निवेशक बिल एकमैन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रॉयटर्स ने एकमैन के हवाले से लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बेहद विश्वसनीय और अच्छी तरह से रिसर्च कर तैयार की गई है। हालाँकि उन्होंने दूसरे निवेशकों को आगाह भी किया कि क्योंकि उन्होंने ख़ुद स्वतंत्र तौर पर अदानी समूह पर रिसर्च नहीं की है, इसलिए इसे निवेश सलाह के रूप में न लिया जाए।

हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप

- ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से निवेश।
- ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल।
- पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा, कारोबार बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया।
- परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे, विवादों से जुड़ाव।
- खातों में गड़बड़ी इसीलिए 08 साल में 4 सीएफओ ने इस्तीफा दिया।

हिंडनबर्ग शोध का ट्रैक रिकॉर्ड एक नजर में

सितंबर 2020- निकोला- हिंडनबर्ग ने 'Nikola: How to Parlay An Ocean of Lies Into a Partnership With the Largest Auto OEM in America' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें व्हिसल ब्लोअर और पूर्व कर्मचारियों की मदद से, निकोला द्वारा

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या-क्या हुआ?

हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर अकाउंटिंग फ्रॉड, शेयरों की कीमतों में ओवर प्राइसिंग समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के दाम 85 फीसदी तक अधिक हैं और आज उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अडानी के शेयर 85 फीसदी तक गिर चुके हैं। गौतम अडानी को ही नहीं, उनके निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं गौतम अडानी की निजी संपत्ति गिरकर मात्र 35 अरब डॉलर रह गई है। 24 जनवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में गौतम अडानी का नेटवर्थ 127 अरब डॉलर से गिरकर 35 अरब डॉलर तक गिर गया है। एक महीने में उनकी दौलत दो-तिहाई स्वाहा हो चुकी है। अब गौतम अडानी के पास मात्र 01 तिहाई संपत्ति बच गई है। अगर ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में देखें को गौतम अडानी की संपत्ति गिरकर 40 अरब डॉलर के पास रह गई हैं। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अडानी के शेयरों की कीमत 85 फीसदी तक गिर चुकी है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर जो 23 जनवरी को 3436 रुपये पर बंद हुए थे वो 60 फीसदी गिरकर 1382.65 रुपये पर पहुंच गए। अडानी टोटल के शेयर जो 23 जनवरी को 3901 रुपये पर बंद हुए थे, वो 80 पीसदी गिरकर 791 रुपये पर बंद हुआ। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर जो एक महीने पहले 1932 रुपये पर थे, गिरकर 512 रुपये पर पहुंच चुके हैं। ये गिरावट सिर्फ नंबर नहीं है। ये दिखाते हैं कि अडानी के निवेशकों को इस रिपोर्ट से कितना बड़ा नुकसान हुआ है।

कथित झूठ और धोखे का पर्दाफाश किया था। हिंडनबर्ग वेबसाइट ने दावा किया है कि इस रिपोर्ट के बाद निकोला के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवर मिल्टन ने तुरंत कंपनी से इस्तीफा दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, सीएनएन, बैरन्स और सीएनबीसी सहित अन्य में

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रची थी अडानी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की इबारत

चित्रित इस कहानी ने कथित तौर पर मुख्यधारा के अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। एसईसी और डीओजे दोनों ने रिपोर्ट के बाद कंपनी में जांच की सूचना दी।

जून 2020- विन्स फाइनेंस- हिंडनबर्ग ने WINS Finance के बारे में लिखा, यह

02 नंबर से 29वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दोनों दुनिया के अमीरों की लिस्ट में नीचे फिसलते जा रहे हैं। गौतम अडानी अब इस लिस्ट में लुढ़कर सीधे 29वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी अब 12वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। दोनों की नेटवर्थ में गिरावट आई है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गौतम अडानी को हुआ है। गौतम अडानी की नेटवर्थ लगातार कम हो रही है। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी लगातार नीचे लुढ़कते जा रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि गौतम अडानी की नेटवर्थ में काफी उछाल आई थी। इस दौरान उनकी नेटवर्थ 150 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई थी और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। यह मुकाम हासिल करने वाले वह एशिया के पहले शख्स थे, लेकिन इस साल अडानी की नेटवर्थ में भारी गिरावट आई है। गौतम अडानी लगातार दौलत गंवा रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, गौतम अडानी की नेटवर्थ अब 42.7 अरब डॉलर रह गई है। इसी के साथ वो ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में 29वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी मुकेश अंबानी की तुलना में 14 गुना दौलत गंवा चुके हैं। दोनों अरबपति इस साल अब तक दौलत गंवाने के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसी वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ में 3.39 अरब डॉलर की कमी आई है।

मुकेश अंबानी पहुंचे 12वें नंबर पर- बाजार में गिरावट मुकेश अंबानी पर भी भारी पड़ी है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को भी काफी नुकसान हुआ है। आरआईएल के शेयर 2.35 फीसदी टूटकर 2377 रुपये पर बंद हुए हैं। इससे मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में भी गिरावट आ गई है। इस दौरान मुकेश अंबानी ने 1.96 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवा दी है। अंबानी अब ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में लुढ़कर अब 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले वो 11वें नंबर पर थे। मुकेश अंबानी अब तक 5.65 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवा चुके हैं। अब मुकेश अंबानी के पास 81.5 अरब डॉलर की दौलत है। इस हिसाब से देखें तो गौतम अडानी के मुकाबले मुकेश अंबानी के पास दोगुनी दौलत है।

इंगित करते हुए कि चीन में एक कंपनी की सहायक कंपनी 350 मिलियन डॉलर की परिसंपत्ति फ्रीज के अधीन थी जिसका खुलासा अमेरिकी निवेशकों को नहीं किया गया था। हिंडनबर्ग ने यह भी बताया कि WINS के माता-पिता, जिनके पास 67.7प्रतिशत WINS की इक्विटी थी, को पहले ही चीन में दिवालिया घोषित कर दिया गया था और अमेरिकी निवेशकों को कोई

अंबानी-दमानी ने भी गंवाई अपनी दौलत

तीन अरबपतियों को नुकसान- गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और राधाकिशन दमानी तीन ऐसे टॉप भारतीय अरबपति हैं, जिन्होंने इस साल बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि, अंबानी और दमानी की तुलना में, अडानी की नेटवर्थ को कई गुना नुकसान हुआ है। 04 फरवरी तक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी लगभग 59 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में 21 वें स्थान पर हैं। वो इस साल अब तक अपनी 62 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवा चुके हैं।

कितनी घटी अंबानी और दमानी की संपत्ति- वहीं, मुकेश अंबानी फिलहाल 80 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन उन्हें साल-दर-साल के आधार पर 6.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके बाद वेन्यू सुपरमार्ट्स के संस्थापक राधाकिशन दमानी आते हैं, जिनकी कुल संपत्ति वर्तमान में लगभग 16.7 बिलियन डॉलर है। साल-दर-साल आधार पर उनकी संपत्ति में 2.61 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है।

अडानी के शयरों में 50 फीसदी की गिरावट- हिंडनबर्ग के रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। अडानी समूह की कंपनियों ने एक्सचेंजों पर सात कारोबारी सत्रों में कुल 9 लाख करोड़ रुपये का एम-कैप गंवा दिया। अडानी टोटल गैस के शेयर इस अवधि के दौरान 3,885.45 रुपये से सबसे अधिक 51 फीसदी गिरकर 1901.65 रुपये पर आ गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी (40 प्रतिशत नीचे), अडानी एंटरप्राइजेज (38 प्रतिशत नीचे), अडानी ट्रांसमिशन (37 प्रतिशत नीचे), अडानी पोर्ट्स और एसईजेड (35 प्रतिशत नीचे), अंबुजा सीमेंट्स (33 प्रतिशत नीचे), अडानी विल्मर (23 प्रतिशत नीचे), अडानी पावर (22.5 प्रतिशत नीचे), एसीसी (21 प्रतिशत से नीचे) और एनडीटीवी (17 प्रतिशत से नीचे) में भारी गिरावट आई।

खुलासा नहीं किया गया था। लगभग चार महीने बाद, अक्टूबर 2020 में, NASDAQ ने WINS को विशेष रूप से अधोषित संपत्ति फ्रीज हिंडनबर्ग की पहचान के कारण हटा दिया। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि जीनियस ब्रांड्स, जो उस समय लगभग 6.86 डॉलर प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, अत्यधिक खुदरा उत्साह और लंबित कमजोर पड़ने के कारण जल्द ही 1.50

घनश्यामदास बिड़ला

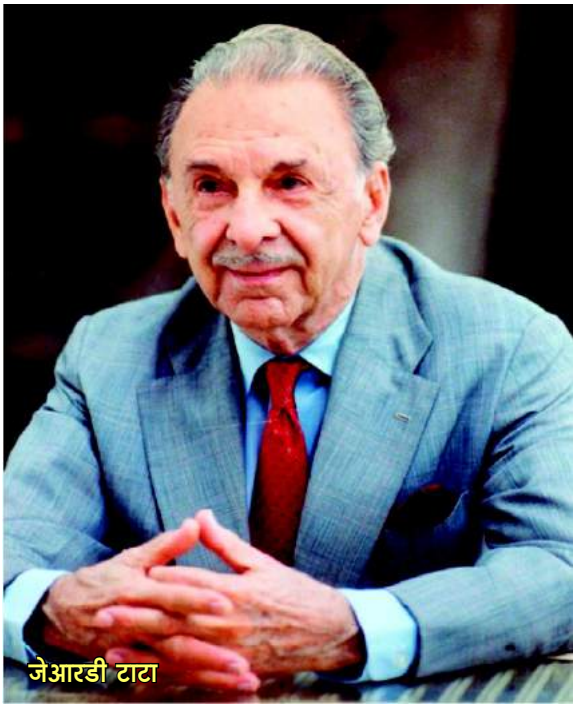
जेआरडी टाटा

जेआरडी टाटा, घनश्यामदास बिड़ला जैसे देश के उद्योगपतियों ने देशभक्ति और देश की तरक्की में काफी योगदान दिया है। यहां तक कि भारत की आजादी में भी इनका अमूल्य योगदान रहा है। इन जैसे उद्योगपतियों ने देश को हमेशा आगे रखा और बाद में स्वयं को।

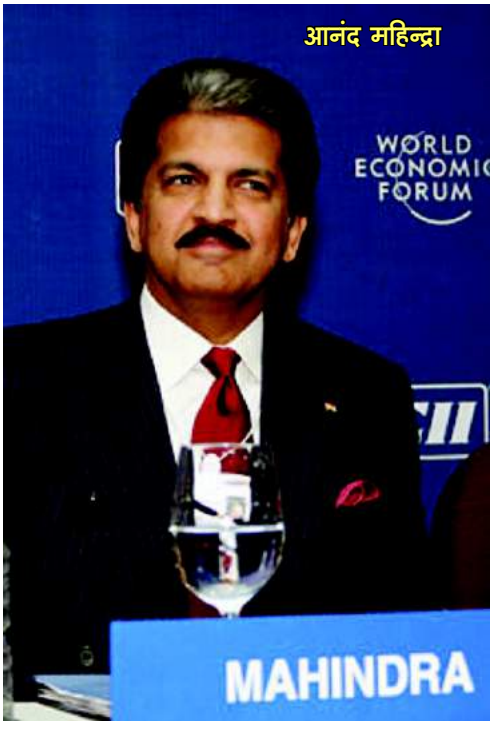

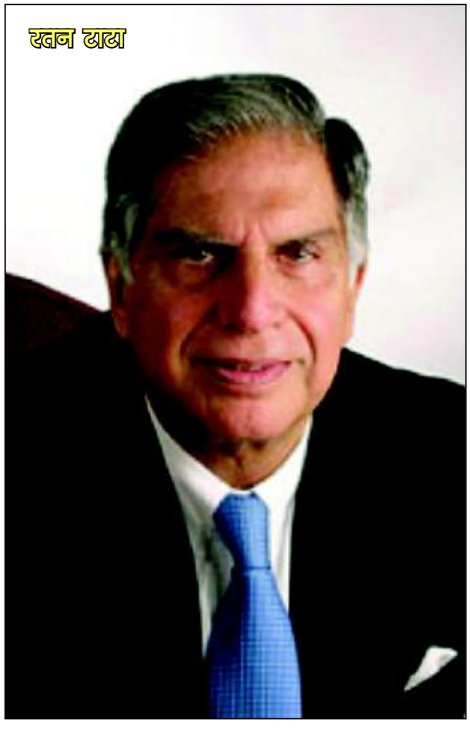

डॉलर का स्टॉक बन जाएगा। जुलाई के अंत तक, ठीक दो महीने बाद, शेयर 1.50 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे, लगभग 80 प्रतिशत की गिरावट। 2021 में, जीनियस ब्रांड्स निवेशकों के एक समूह ने प्रतिभूति धोखाधड़ी का मुकदमा ख़ारिज करवा लिया था।

मई 2020- चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन- हिंडनबर्ग ने चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के बारे में दिखाया कि कैसे कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में थी और कई लेखांकन अनियमितताओं की पहचान की, जिसमें अघोषित संबंधित पार्टी लेनदेन के साक्ष्य शामिल थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के महीनों बाद,

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी केस में एक्सपर्ट कमेटी बनाई

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 06 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी से भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी।

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इन 2 पहलुओं की जांच करेगी- शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। यानी मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग की निगरानी और पुख्ता की जाएगी। अडाणी ग्रुप के शेयर्स में तेज गिरावट से जुड़े विवादों की जांच करेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ग्रुप के शेयर्स गिरे थे।

कमेटी के अलावा सेबी भी 02 पहलुओं की जांच करेगी- क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19 का उल्लंघन हुआ? क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिए हैं

- सेबी के चेयरपर्सन को एक्सपर्ट कमेटी को सभी जरूरी जानकारी देनी होगी।
- केंद्र सरकार से जुड़े एजेंसियों को कमेटी के साथ सहयोग करना होगा।
- कमेटी अपने काम के लिए बाहरी विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है।
- कमेटी मेंबर्स का पेमेंट चेयरपर्सन तय करेंगे और केंद्र सरकार वहन करेगी।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सीनियर ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगी।
- ये कमेटी को लॉजिस्टिकल असिस्टेंस देने के लिए नोडल ऑफिसर के रूप में काम करेंगे।
- कमेटी के सभी खर्चो को केंद्र सरकार ही वहन करेगी।

अडाणी-हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं 4 याचिकाएं - इस मामले में अभी तक 04 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और एफआईआर की मांग की है। इसके साथ ही इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक की भी मांग की गई थी। विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की। तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों के उन हालातों के बारे में बताया जब शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं। जया ठाकुर ने इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका पर संदेह जताया है। उन्होंने एलआईसी और एसबीआई की अडाणी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच की मांग की है। मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में सेबी, ईडी, आयकर विभाग, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की मांग की है। मुकेश कुमार ने अपने वकीलों रूपेश सिंह भदौरिया और महेश प्रवीर सहाय के जरिए ये याचिका दाखिल कराई है।

सुप्रीम कोर्ट ने केस के मीडिया कवरेज पर रोक से इनकार किया- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। वहीं कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इसे सुनाया जाएगा।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को नुकसान- याचिकाओं में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इसमें ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया और हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन भी भारतीय नियामक सेबी को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे।

अर्न्स्ट एंड यंग ने लेखांकन मुद्दों और अघोषित संबंधित पार्टी लेनदेन की पहचान करने पर ऑडिट राय जारी करने से इनकार करने के बाद लेखा परीक्षक के रूप में वापस ले लिया। रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयर 90त्न से अधिक गिर गए।

हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ अडानी परिवार के सदस्यों का खुलासा

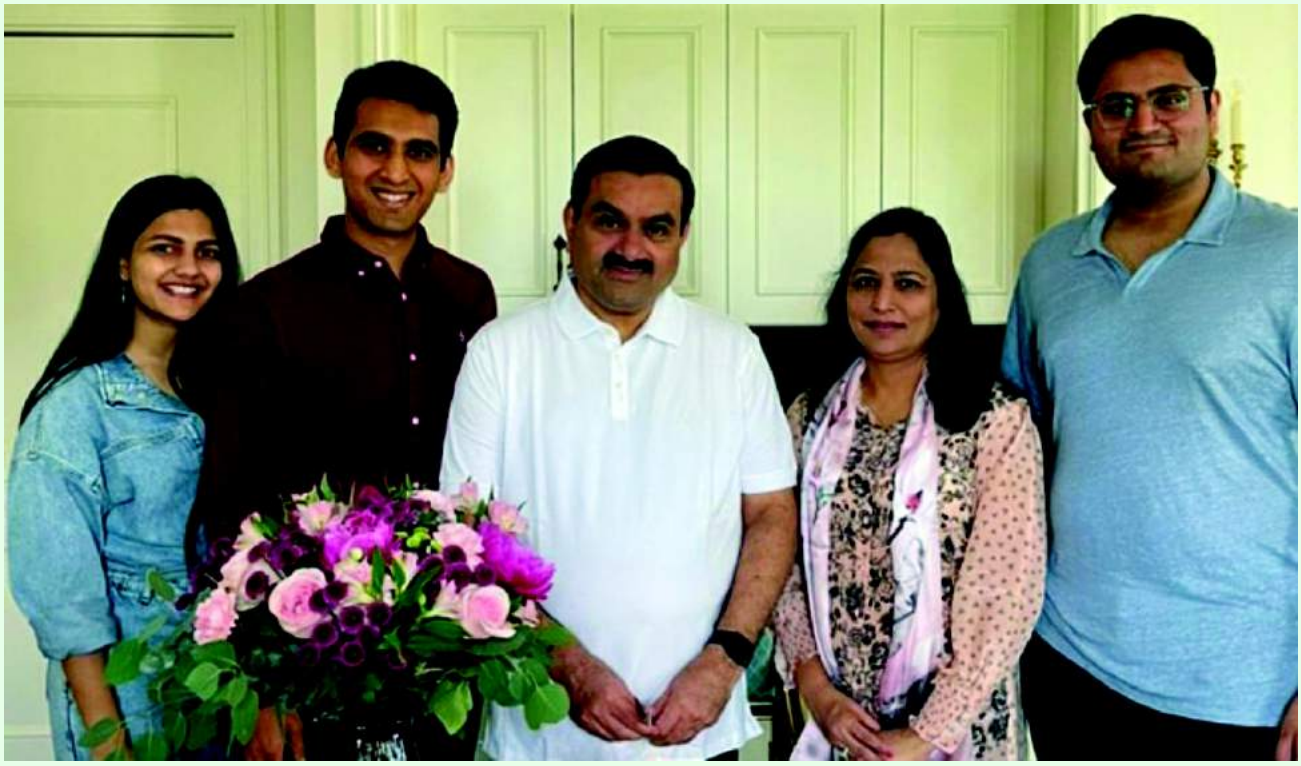

106 पन्नों की इस रिपोर्ट में अडानी परिवार के और भी सदस्यों के नाम हैं, जिसमें गौतम अडानी के अलावा विनोद अडानी, राजेश अडानी, समीर वोरा, जतिन मेहता और प्रीति अडानी का नाम शामिल है।

कौन हैं विनोद अडानी ?- विनोद अडानी गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनोद अडानी ऑफशोर शेल कंपनियों के एक विशाल चव्यूह का मैनेजमेंट करते हैं। हाल ही में जारी हुई IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022 के मुताबिक विनोद शांतिलाल अडानी सबसे अमीर एनआरआई बनकर उभरे हैं। विनोद अडानी का नाम 2016 में पनामा पेपर लीक और 2021 में पेंडोरा पेपर लीक में सुर्खियों में आया था।

अप्रैल 2020- एससी वर्क्स-हिंडनबर्ग ने SC Wor& (NASDAQ: WORX) के बारे में लिखा, जिसमें कहा गया था कि कंपनी द्वारा घोषित कोविड-19 परीक्षण सौदा पूरी तरह से फर्जी लग रहा था। हिंडनबर्ग ने सीईओ के बारे में भी सवाल उठाए, जो एक सजायाफ्ता अपराधी है, और कंपनी के दावा किए गए कोविड-19 परीक्षण भागीदार का ट्रैक रिकॉर्ड है,

राजेश अडानी

विनोद अडानी

कौन हैं राजेश अडानी?- राजेश अडानी गौतम अडानी के छोटे भाई हैं। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट के में राजेश अडानी पर आरोप है कि उन्होंने हीरों की ट्रेडिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम में मुख्य भूमिका निभाई है और वो 1999 और 2010 में दो बार अरेस्ट हो चुके हैं। राजेश अडानी इन दिनों अडानी ग्रुप कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं।

कौन हैं समीर वोरा?- समीर वोरा गौतम अडानी के बहनोई हैं। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट में इस हीरा घोटाला में समीर वोरा का भी बड़ा हाथ बताया गया है। रिपोर्ट में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने लगातार अपने गलत बयानों के कारण ट्रेडिंग में घोटाला किया है। समीर वोरा इन दिनों अडानी के ऑस्ट्रेलिया डिवीजन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं।

अडानी ग्रुप से पूछे गए 88 सवाल

हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है? उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप है। हिंडनबर्ग ने पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब अब तक अदानी ग्रुप ने नहीं दिया है।

गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने शेल कंपनियों के ज़रिये अडानी समूह का विस्तार किया

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद निशाने पर आए अडानी समूह के संबंध में अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका ने बताया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने विभिन्न ऑफशोर क्षेत्रों में कंपनियों का एक कथित जाल खड़ा किया, जिनके बारे में नियामक अधिकरणों को नहीं बताया गया। विनोद अडानी की अडानी समूह की कंपनियों के विस्तार में केंद्रीय भूमिका रही है। विनोद अडानी मॉरीशस स्थित ऐपोलिस ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के मालिक हैं, जो वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड के 100 फीसदी शेयर का मालिकाना हक रखती है। लेख में दावा किया गया है कि एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्डवाइड के पास अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में 04 बिलियन डॉलर मूल्य का प्रमोटर स्टॉक है। फोर्ब्स ने यह भी कहा कि निवेश पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ट्रेंडलाइन के अनुसार, एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्डवाइड के पास अन्य कोई प्रतिभूतियां नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि रूसी बैंक से पिनेकल का ऋण अडानी कंपनी के शेयरों की कीमत देखते हुए सुरक्षित था। इसमें कहा गया है, किसी भी फंड ने चार अडानी कंपनियों, जिनमें उन्होंने निवेश किया है, के लिए भारतीय वित्तीय फाइलिंग में गिरवी शेयरों का खुलासा नहीं किया है। न तो अडानी समूह और न ही विनोद अडानी ने इस संबंध में कोई जवाब दिया।

जिसे एक दोषी बलात्कारी द्वारा चलाया गया था। SC Wor& को उसी दिन SEC द्वारा रोक दिया गया था जिस दिन प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज ने अप्रैल के अंत में हिंडनबर्ग वेबसाइट पर उल्लेख किया था।

मार्च 2020- प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप हिंडनबर्ग ने प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप की कोविड-19 संबंधित प्रेस विज्ञप्ति पर

सवाल उठाया। कंपनी को अप्रैल 2020 के अंत में कोविड-19 परीक्षणों के दावों के लिए रोक दिया गया था और अब ग्रे शीट्स पर ट्रेड करता है। जब हिंडनबर्ग ने पहली बार एक साल से भी कम समय पहले कंपनी के बारे में लिखा था, तो इसका मार्केट कैप 1 बिलियन डॉलर था। इसके बाद से इसका मूल्य 90 प्रतिशत कम हो गया है।

मार्च 2020- एचएफ फूड्स हिंडनबर्ग ने एचएफ फूड्स के बारे में लिखते हुए बताया कि विशेष रूप से कंपनी के शेयरधारक पूंजी के दुरुपयोग और 509 मिलियन डॉलर विलय सहित बड़े पैमाने पर अघोषित संबंधित पार्टी लेनदेन को बुलावा दिया। 2020 के मई में, HFFG को 338.2 मिलियन डॉलर की हानि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 339.9 मिलियन डॉलर का तिमाही घाटा हुआ। रिपोर्ट की गई हानि और हानि के समय कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 400 मिलियन डॉलर था।

अक्टूबर 2019- स्माइल डायरेक्ट क्लब हिंडनबर्ग ने स्माइल डायरेक्ट क्लब के संदिग्ध व्यवसाय प्रथाओं के ग्राहकों को

आखिर वापस लेना पड़ा एफपीओ

हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब समूह ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का 20,000 करोड़ रुपये का एफपीओ जारी करने का फैसला किया था। रिपोर्ट आने के बावजूद कंपनी ने अपना एफपीओ लॉन्च किया। शुरुआत में इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन आखिरी दिन 31 जनवरी को ये पूरी तरह से सब्साइब हो गया। लेकिन ग्रुप ने अगले ही दिन एक फरवरी को एफपीओ को वापस ले लिया। अडानी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि दिन के कारोबार के दौरान समूह के शेयरों में आए उतार-चढ़ाव के वजह से ये फैसला किया गया।

बैलाडीला की खदान नं. 13:

मोदी ने अडानी को खदान देकर किया था आदिवासियों की आस्था से खिलवाड़

छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक और सम्पन्न राज्य है और राज्य का बस्तर जिला खनिज संपदा के मामले में सबसे अव्वल है। अब इसी खनिज संपदा को लेकर राज्य में बबाल मचा हुआ है। दरअसल बस्तर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और इन आदिवासियों की आजीविका और आस्था जिले में स्थित पर्वत हैं। इन पर्वतों से ही इनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन देश की

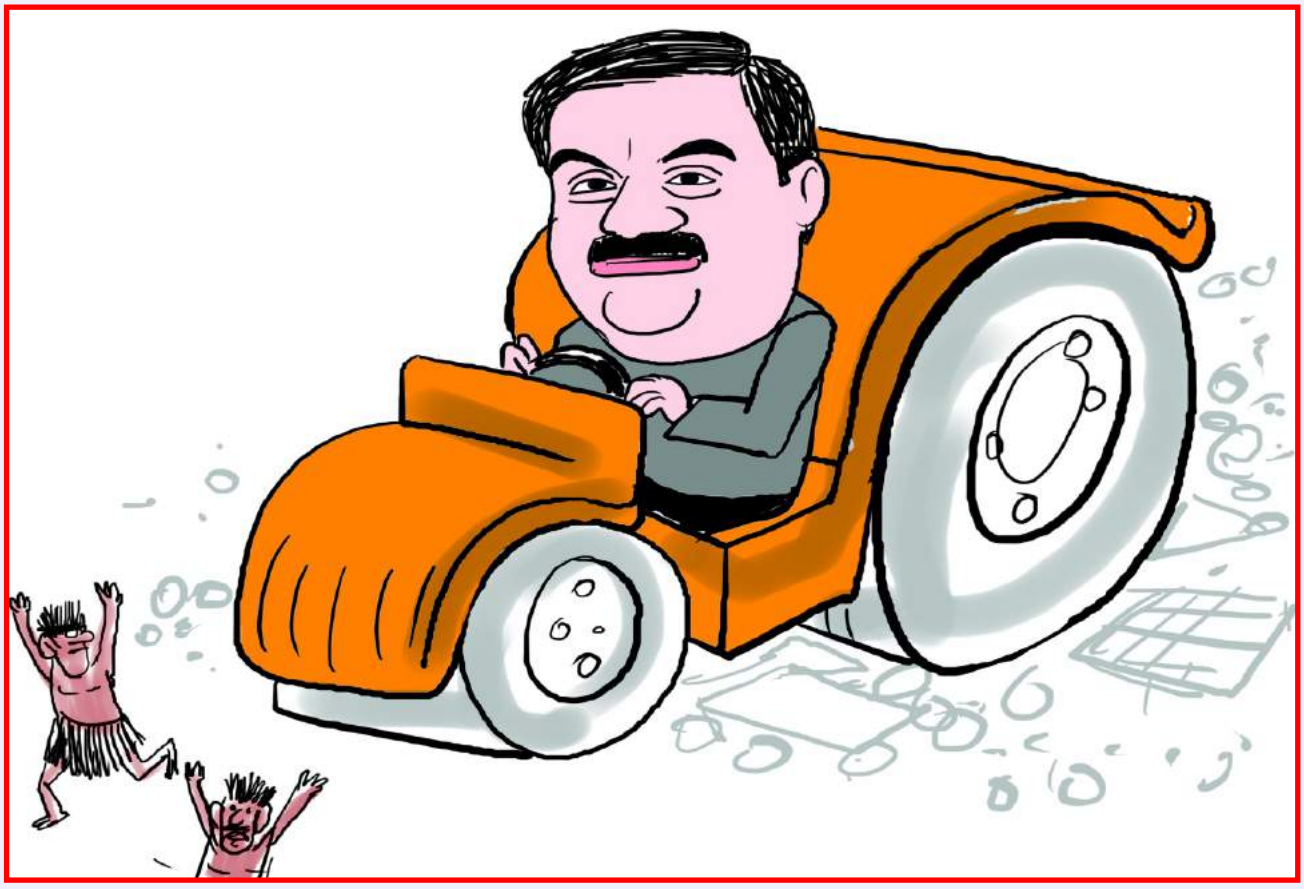

चेतावनी देते हुए एक लेख लिखा और निवेशकों को चेतावनी दी कि खराब ग्राहक समीक्षाओं, मुकदमों, विभिन्न नियामक जांचों और उचित लाइसेंस के बिना दंत चिकित्सा का अभ्यास करने के आरोपों के परिणामस्वरूप कंपनी का नकारात्मक प्रेस फैल सकता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, एक्सपोज़ बोस्टन ग्लोब, न्यूयॉर्क टाइम्स और एनबीसी न्यूज (छिपे हुए कैमरे के

राजनैतिक पार्टियां आदिवासियों के जीवकोपार्जन पर ही कुठाराघात करने पर तुली हुई हैं। इनकी आस्था पर भी प्रहार किया जा रहा है। इनके बजूद के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आखिरकार आदिवासियों ने शक्ति और एकता का परिचय देकर अपनी आस्था और आजीविका को बचा लिया है। बैलाडीला की खदान नं. 13 को अडानी ग्रुप को दिये जाने के विरोध में आदिवासियों ने जो बृहद स्तर पर आंदोलन किया था, उससे सरकार को झुकना पड़ा और आदिवासियों की जीत हुई। यह वही पहाड़ी है जिस पर आदिवासियों के इष्टदेव नंदराज विराजमान है, जिन्हें ये लोग पूजते हैं। हालांकि नंदराज पर्वत की खदान 13 को अडानी को लीज पर दिये जाने का

फुटेज और ग्राहक प्रशंसापत्र के साथ पूर्ण) द्वारा लिखे गए थे, जो मूल रूप से हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते थे।

सितंबर 2019- ब्लूम एनर्जी-हिंडनबर्ग ने एक लेख लिखा था जिसमें बताया गया था कि ब्लूम एनर्जी के अघोषित ऑफ-बैलेंस शीट देनदारियों में अरबों डॉलर थे। हिंडनबर्ग ने विशेष रूप से

मामला नया नही है। 2014 से ही जब से केन्द्र में मोदी की सरकार बनी है तब से ही अडानी की गिद्ध दृष्टि इस पर थी। क्योंकि इस खदान में बहुत प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध है। केन्द्र में मोदी और राज्य में भाजपा सरकार होने का पूरा लाभ अडानी को मिला और गलत प्रक्रिया के तहत अडानी ने यह खदान हथिया ली। फर्जी ग्रामसभा सरकार आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डाल दिया। यहां नरेन्द्र मोदी की गौतम अडानी के प्रति सहानुभूति और प्रेम साफ झलकता है, लेकिन अब आदिवासियों की एकता ने अडानी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

खदान नंबर 13 का विवाद

राज्य बनने के बाद एनएमडीसी और राज्य सरकार की संस्था छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम यानी सीएमडीसी ने 2008 में मिलकर लौह अयस्क के उत्खनन के लिये एनसीएल नामक कंपनी बनाई। बैलाडीला की खदानों में से एक डिपोज़िट 13 के लौह उत्खनन का प्रस्ताव 2011 में केंद्र सरकार की फ़ॉरेस्ट एडवाइज़री कमेटी को भेजा गया। इस डिपोज़िट में 350 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार होने का अनुमान है, लेकिन फ़ॉरेस्ट एडवाइज़री कमेटी ने अपनी बैठक में इस खदान को अनुमति देने से साफ़ इंकार कर दिया। कमेटी का तर्क था कि जिस पहाड़ में खनन का प्रस्ताव दिया गया है, वह अत्यंत उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। इसके अलावा इसका पूरा वन क्षेत्र अब तक अछूता है। 26 अगस्त 2011 को फ़ॉरेस्ट एडवाइज़री कमेटी ने इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया। इसके बाद नये सिरे से 05 जून 2013 को राज्य की भाजपा सरकार द्वारा फिर से इस खदान के उत्खनन का प्रस्ताव फ़ॉरेस्ट एडवाइज़री कमेटी को भेजा गया, लेकिन बात फ़ाइलों में अटकी रही। इसके बाद केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद 12 नवंबर 2014 को पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनएमडीसी को पहले फ़ेज़ में 315.813 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन की अनुमति दे दी। इसके अलावा 09 जनवरी 2017 को दूसरे फ़ेज़ की अनुमति भी एनएमडीसी को दे दी गई। चार साल पहले के उच्च जैव विविधता और अछूते वन के दावे ख़ुद ही सरकार ने ख़ारिज कर दिये। इसके बाद एनएमडीसी ने एमडीओ यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के बतौर इस खदान को अडानी इंटरप्राइजेज को सौंप दिया।

नंदराज पहाड़ को बचाने के लिए बैलाडीला में कई दिनों से चला रहा आदिवासियों का आंदोलन आखिरकार रंग ले आया। राज्य सरकार ने आदिवासियों की कुछ मांगों को मानते हुए वनों की कटाई पर रोक लगा दी। साथ ही क्षेत्र में संचालित कार्यों को भी रोकने के निर्देश दिए हैं। नंदराज पहाड़ को बचाने के लिए बैलाडीला की डिपॉजिट 13 खदान के विरोध में आदिवासियों का आंदोलन 07 जून 2019 से जारी था। आंदोलन में करीब 40 हजार आदिवासी मौजूद थे। संभाग भर से आदिवासी जंगलों से निकलकर अपने परिवार सहित मीलों पैदल यात्रा कर इस आंदोलन में शामिल हुए थे। आदिवासियों के आंदोलन को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। हालांकि आदिवासियों ने मामला खत्म होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। बस्तर सांसद दीपक बैज और कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम के साथ प्रतिनिधि मंडल ने आदिवासियों की स्थिति और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री बघेल के सामने रखा था। सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगाने के साथ ही मामलों की जांच कराने और कार्रवाई करने, विवादित क्षेत्र में संचालित सभी कार्यों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। जंगल की कटाई पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश, साल 2014 के ग्रामसभा के आरोप की जांच कराने के निर्देश, इलाके में संचालित कार्यों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश, राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखकर जन भावनाओं की जानकारी दी जाएगी।

हालांकि कांग्रेस-भाजपा दोनों पार्टियों के नेता इस पहाड़ी को अडानी को लीज पर दिए जाने के मामले में आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आदिवासियों के इस विरोध का समर्थन आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी के अलावा कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़

कंपनी के लेखांकन से संबंधित मुद्दों को अपने सेवा समझौतों के आसपास बताया। हिंडनबर्ग लेख के लगभग 05 महीने बाद, ब्लूम ने सार्वजनिक होने के बाद से हर तिमाही में शामिल अपने सेवा समझौतों से संबंधित भौतिक लेखांकन त्रुटियों के कारण अपने वित्तीयों के लगभग चार वर्षो के बड़े पैमाने पर पुनर्कथन की घोषणा की। फोर्ब्स ने कंपनी पर एक संबंधित खुलासा

(जे), आम आदमी पार्टी, सीपीआई जैसे राजनीतिक दल कर रहे हैं।

मालूम हो कि अडानी समूह ने सितंबर 2018 को बैलाडीला आयरन और माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी बीआईओएमपीएल नाम की कंपनी बनाई और दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने इस कंपनी को बैलाडीला में खनन के लिए 25 साल के लिए लीज दे दी। बैलाडीला की डिपॉजिट 13 नंबर पहाड़ के 315.813 हेक्टेयर रकबे में लौह अयस्क खनन के लिए वन विभाग ने वर्ष 2015 में पर्यावरण क्लीयरेंस दे दिया है, जिस पर एनएमडीसी और राज्य सरकार की छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सीएमडीसी) को संयुक्त रूप से उत्खनन करना था। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत संयुक्त उपक्रम एनसीएल का गठन किया गया था, लेकिन बाद में यह लीज निजी कंपनी अडानी इंटरप्राइसेस लिमिटेड को 25 साल के लिए हस्तांतरित कर दी गई। बताया जा रहा है कि डिपॉजिट-13 पहाड़ के 315.813 हेक्टेयर रकबे में 326 मिट्रिक टन लौह अयस्क होने का पता सर्वे में लगा है। इस अयस्क में 65 से 70 फीसदी आयरन की मात्रा पायी जाती है।

आदिवासियों का यह विरोध सिर्फ खनन या अडानी को इसे लीज पर दिए जाने का नहीं है। यहां सवाल आस्था से जुड़ी आदिवासियों की उन प्राचीन मान्यताओं का है, जिन्हें वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी से मानते आ रहे हैं।बैलाडीला की डिपॉजिट 13 नंबर पहाड़ को नंदराज पर्वत कहा जाता है। आदिवासियों के अनुसार, इस देव स्थान पर दो पहाड़ हैं, नंदराज पहाड़ और उसके सामने का पहाड़ पिट्टोड़ मेटा देवी का पहाड़ है, जिसे वे पूजते हैं।

क्या मानते हैं आदिवासी ?

जल, जंगल, जमीन के लिए ही आदिवासी जीते हैं। सरकार इसे ही छीनने की कोशिश कर रही है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर ज़िलों सहित पड़ोसी राज्य ओडिशा और महाराष्ट्र के हज़ारों आदिवासियों के देवताओं का घर नंदराज पर्वत है और यह आदिवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। आदिवासी किसी के भी द्वारा इस नंदराज पर्वत की खुदाई के सख्त खिलाफ हैं। जिस डिपॉजिट 13 की खुदाई का ठेका अडानी समूह की कंपनी को दिया गया है, वो आदिवासी देवता नंदराज की पत्नी पिट्टोड़ रानी का मायका भी है। ऐसे में इस पहाड़ी का आदिवासियों के लिए धार्मिक महत्व है। इसकी खुदाई किसी को भी नहीं करने देंगे। आदिवासी देवताओं की इस पहाड़ी को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।

बस्तर की परिस्थितियों और संस्कृति को लेकर बस्तरनामा, आमचो बस्तर, लाल अंधोरा, बस्तर के जननायक समेत 14 किताबें लिख चुके राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं बैलाडिला की सुलगन गंभीर है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एनएमडीसी लि. जो कि दशकों से लौह उत्खनन कर रहा है, इसे दरकिनार कर क्षेत्र में अडानी समूह को खुली खदान दिया जाना, विरोध के स्वर उत्पन्न कर रहा है। यदि नियमगिरि का सबक नहीं लिया गया है तो बैलाडीला अधिक गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। जन जातीय क्षेत्रों में कार्य करते हुए यदि आप स्थानीय देवी-देवता, जन-मान्यता, लोक-जीवन व संस्कृति की उपेक्षा कर विकास की अपनी ही परिभाषा गढ़ने का प्रयास करेंगे तो बैलाडीला डिपॉजिट 13 को लेकर आरम्भ हुआ जन-प्रतिरोध स्वाभाविक है। राजीव कहते हैं कि भावनात्मक विषयों को विकास की किसी परिपाटी में सही ठहराने का प्रावधान नहीं है। यह प्रकरण अधिक गंभीर होता जा रहा है। चूंकि परोक्ष रूप से ही सही राजनीति की छाया इस पर मंडराने लगी है। राजनैतिक दलों ने नफा-नुकसान टटोलने आरम्भ कर दिये हैं।

ये है पूरा मामला

दरअसल दंतेवाड़ा के बैलाडीला पर्वत श्रृंखला के नंदराज पहाड़ पर स्थित एनएमडीसी की डिपॉजिट-13 नंबर खदान को अडानी की कंपनी को दिए जाने के बाद होने वाले खनन का विरोध आदिवासियों ने शुरू कर दिया था। नंदराज पहाड़ को बचाने के लिए सर्व ग्राम पंचायत ने आंदोलन की तैयारी कर ली थी। जन संघर्ष समिति के बैनर तले आदिवासी एनएमडीसी का घेराव कर रहे थे। डिपॉजिट 13 के निजीकरण का शुरू से विरोध कर रहे ट्रेड यूनियन भी आंदोलन के समर्थन में थी।

प्रकाशित किया।

दिसंबर 2018- यांग्त्ज़ी रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स- हिंडनबर्ग ने यांग्त्ज़ी रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में एक लेख लिखा, जो चीन स्थित 02 बिलियन डॉलर मार्केट कैप वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी है। हिंडनबर्ग की जांच में पाया गया कि अन्य प्रमुख विसंगतियों के बीच कंपनी की प्रमुख संपत्ति मौजूद नहीं थी। कंपनी ने

अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की आयी रिपोर्ट के बाद संसद से लेकर सड़क तक अडानी का विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही मोदी सरकार को तमाम विपक्षी दलों ने कटघरे में खड़ा किया।

मानहानि का आरोप लगाते हुए हिंडनबर्ग पर मुकदमा दायर किया। कई स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स और एक कानूनी फर्म ने हिंडनबर्ग के रिपोर्टिंग की पुष्टि की। कंपनी को 6 महीने बाद NASDAQ से हटा दिया गया था, इसके मार्केट कैप का 98 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ था। हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा बाद में खारिज कर दिया गया था।

दिसंबर 2018- लिबर्टी हेल्थ साइंसेज हिंडनबर्ग ने लिबर्टी हेल्थ साइंसेज और एफयिां के बीच अनियमित अधिग्रहण और व्यवहार के बारे में एक लेख लिखा था। लेख के बाद, लिबर्टी के चार निदेशकों ने अपने सीईओ और सीएफओ के साथ इस्तीफा दे दिया। 2020 में, लिबर्टी हेल्थ साइंसेज ने कहा कि यह क्लास-एक्शन सूट को निपटाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है। निपटान का आंकड़ा कथित तौर

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी ने केन्द्र की मोदी सरकार और गौतम अडानी को जमकर घेरा। आप के नेता संजय सिंह ने मुखर होकर इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया और जगह-जगह प्रदर्शन किये।

पर 1.8 मिलियन डॉलर था। आपको बता दें कि विश्व के अन्य देश अपने देश की खनिज संपदा को संभालकर रखते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता।

दिसंबर 2018- एफक्रिंया हिंडनबर्ग ने एक लेख लिखा था जिसमें बताया गया था कि एफक्रिंया ने अत्यधिक अनियमित, अधिक मूल्य वाले अधिग्रहणों की एक और श्रृंखला बनाई है। एक बार फिर, अंदरूनी सूत्रों ने बाद में अपने स्वयं के अधिग्रहणों में अघोषित हिस्सेदारी होने की बात स्वीकार की, जिसके कारण कंपनी के अध्यक्ष सीईओ, एक सह-संस्थापक और एक कार्यकारीबोर्ड शेक-अप का इस्तीफा हो गया। हिंडनबर्ग ने पहले एक लेख लिखा था जिसमें दिखाया गया था कि ´2 बिलियन मार्केट कैप कैनबिस कंपनी Aphria ने अत्यधिक अनियमित, ओवरवैल्यूड अधिग्रहण किया था। कंपनी ने बाद में स्वीकार किया कि अंदरूनी सूत्रों ने

गौतम अडानी का विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के अन्य देशों में जहां अडानी की कंपनियां संचालित है वहां भी अडानी समूह का विरोध किया जाता रहा है। ऐसा ही एक विरोध 2020 में आस्ट्रेलिया में देखा गया था।

अधिग्रहण लक्ष्य नुवेरा में निजी हिस्सेदारी का खुलासा किया था।

दिसंबर 2017- रायट ब्लॉकचैन हिंडनबर्ग ने रायट ब्लॉकचैन के संदिग्ध अधिग्रहण के बारे में लेखों की एक श्रृंखला लिखी जो अंदरूनी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। बाद में फरवरी 2018 में CNBC ने एक एक्सपोज़ चलाया, जिसने हिंडनबर्ग के निष्कर्षो की पुष्टि और विस्तार किया। रायट के तत्कालीन सीईओ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। जैसा कि हिंडनबर्ग वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है, इसके पूर्व सीईओ कथित तौर पर अब सक्रिय आपराधिक जांच के अधीन हैं।

दिसंबर 2017- पोलारिटीटीई हिंडनबर्ग ने पोलारिटीटीई के बारे में एक लेख लिखा था, जो अनियमित वित्तीय खुलासे के बारे में था। कंपनी के सीएफओ ने बाद में इस्तीफा दे दिया और एसईसी द्वारा 2018 में पंप और डंप योजनाओं में कथित रूप से भाग लेने का आरोप लगाया गया।

नवंबर 2017- ओपको हेल्थ-हिंडनबर्ग ने 03 बिलियन डॉलर मार्केट कैप ओपको हेल्थ के नापाक आपराधिक संबंधों के साथ-साथ उत्पाद विफलताओं और अनियमित प्रकटीकरणों के बारे में एक लेख लिखा। 2018 के अंत में कंपनी के अध्यक्ष सीईओ और कंपनी पर ही SEC द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। बाद में उन्होंने आरोप तय कर दिए।

नवंबर 2017- पर्शिंग गोल्ड-हिंडनबर्ग ने पर्शिंग गोल्ड के बारे में एक लेख लिखा और अनियमित कंपनी खुलासे की एक श्रृंखला के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति की पहचान की। उस व्यक्ति को बाद में SEC (सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन) द्वारा एक समूह के प्राथमिक रणनीतिकार के रूप में चार्ज किया गया था, जिसने कई पंप और डंप स्कीम चलाने का आरोप लगाया था।

2016- आरडी लीगल हिंडनबर्ग के संस्थापक नैट एंडरसन ने एक हेज फंड आरडी लीगल से संबंधित एसईसी को एक व्हिसलब्लोअर रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे बाद में आयोग ने अपने निवेशकों को कथित रूप से गलत बयान देने के लिए आरोपित किया था। आरडी लीगल बाद में मुकदमे में हार गया, जिसके कारण इसके संस्थापक पर जुर्माना और उद्योग निलंबन लगा।

मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी के मायने

नीरज दिवाकर

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार कर ही लिया। लगभग एक साल की जांच पड़ताल के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में तलब किया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिर सवाल उठता है कि सीबीआई को इतना जल्दी गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी। जबकि देखा गया था कि देश के अंदर बड़े-बड़े मामले चल रहे हैं, जहां की तहकीकात करने की फुर्सत ही नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही यह संभावना जताते रहे है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले मामले में भ्रष्टाचार करने और सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अभी भी इसी बात की दुहाई दे रहे है कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है और उनके खिलाफ केन्द्र सरकार ने विद्वेश की भावना से प्रेरित होकर बदले की कार्यवाही की है। आप नेताओं का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। गौरतलब है कि इसके पूर्व केजरीवाल सरकार के जेल मंत्री सत्येन्द्र जैन भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। आप नेताओं का कहना है कि चार्जशीट में नाम न होने के बाद भी सिसौदिया को गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल, सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिनेश अरोड़ा का नाम सबसे अहम माना जा रहा है। अरोड़ा सिसोदिया का करीबी था। अब वह सरकारी गवाह बन गया है।

क्या है दिल्ली की नई शराब नीति?

केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री, लाइसेंस जारी करने और ठेके-बार के संचालन के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इस नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी और नई नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए थे। इस नीति के कारण दिल्ली सरकार पर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे जबकि छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचने की बात कही गई। नई शराब नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्तरां को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। इन्हें छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह शराब परोसने की छूट दी गई थी। जबकि पुरानी नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी। इतना ही नहीं, बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर पाबंदी हटा ली गई थी। नई शराब नीति पर आपत्ति जताए जाने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी समीक्षा की थी। उनका कहना था कि नई नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया में जान-बूझकर खामियां की गईं ताकि लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और इसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित हुए। इसमें से करीब 650 दुकानें खुल गई हैं। यानी हर जोन में 25 से 26 दुकानें। एक जोन के तहत 8-9 वार्ड शामिल किए गए। ऐसे में हर एक वार्ड में 3 शराब की दुकानें। इसके जरिए हर इलाके में शराब आसानी से उपलब्ध हो रही है और शराब को बढ़ावा मिल रहा है। इतना ही नहीं यह भी आपत्ति जताई गई कि नई नीति के जरिए बाजार में केवल 16 कारोबारियों को इजाजत दी जा सकती है और इससे मोनोपॉली को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में शराब की बिक्री करने वाले कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। वो आरोप लगा चुके हैं कि बड़े कारोबारी अपने यहां भारी छूट देते रहे हैं और ऐसे में कारोबार कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।

अरोड़ा ने ही सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपितों के नाम लिए हैं। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया से अन्य आरोपितों व डिजिटल सबूतों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। दरअसल, शराब घोटाले के आरोपितों ने 170 फोन बदले थे। इसमें से सिसोदिया ने 14 फोन बदले थे। जाँच एजेंसियों का मानना है कि इन फोन में ही अहम सबूत थे। इसलिए सिसोदिया समेत अन्य आरोपितों ने या इन्हें तो बदल दिया या तोड़ दिया। अब सीबीआई तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। हालांकि, सत्येंद्र जैन को ईडी ने एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री जैन 2015-16 में कोलकाता की एक फर्म के साथ हवाला लेनदेन में शामिल थे। हवाला प्रणाली में दो पक्ष शामिल होते हैं जो बिना धन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से गुजारते हुए स्थानीय एजेंटों के साथ पैसे का लेन-देन करते हैं।

29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की शराब से कमाई 1.75 लाख करोड़

आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 के दौरान, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल दिल्ली और पुडुचेरी ने शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क के जरिए 1,75,501-42 करोड़ रुपए जुटाए थे। यह डेटा 2018-19 के दौरान इन राज्यों द्वारा जुटाए गए 1,50,657-95 करोड़ से 16 प्रतिशत ज्यादा था।

दिल्ली की 850 दुकानों को लाइसेंस देने से 8,900 करोड़ की कमाई

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अकेले लाइसेंस की नीलामी से 8,900 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह नीलामी के लिए सरकार के रखे बेस प्राइस से लगभग 26-7 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा 15 सितंबर को मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि नई पॉलिसी से सरकार को 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जिससे दिल्ली सरकार की कमाई बढ़कर 10 हजार करोड़ हो जाएगी। यहां एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि दिल्ली सरकार को शराब के जरिए दो तरह से टैक्स मिलते हैं- पहलाः रेवेन्यू से, दूसराः दुकानों के लाइसेंस से। दिल्ली सरकार को इस नई नीति के बाद रेवेन्यू बढ़ने की भी उम्मीद है।

हम जानते हैं कि शराब किसी राज्य सरकार के आय का प्रमुख जरिया होता है। ऐसे में 2021-22 के डेटा से यह समझने की कोशिश की है कि किसी राज्य के टोटल रेवेन्यू में शराब से होने वाली कमाई का प्रतिशत कितना है।

केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में लागू की नई शराब नीति

2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क

दिए थे।

▶ दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना।

▶ दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना।

▶ शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर करना।

▶ हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा।

इस नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने ये 5 प्रमुख फैसले लिए

▶ पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई।

▶ इसमें फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी।

▶ अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी।

▶ हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी।

▶ शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा।

पिछले साल से शुरू होती है कहानी

बात पिछले साल जुलाई की है। दिल्ली

के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में जांच की जरूरत बताई थी। पॉलिसी में शराब बेचने के लिए लाइसेंसधारकों को जरूरत से ज्यादा बेनिफिट दिए गए थे। यह भी कहा गया था कि इसमें नियमों की अनदेखी की गई। एलजी ने पाया था कि ऐसा करने में शीर्ष नेता भी शामिल थे। सिसोदिया पर टेंडर दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ देने का आरोप लगाया गया था। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने की बात कही गई थी। एक और आरोप यह था कि 8 नवंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने विदेशी शराब के रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रिवाइज करने का आदेश दिया था। कैबिनेट और एलजी की मंजूरी लिए बिना बीयर पर 50 रुपये प्रति केस इम्पोर्ट पास फीस लेवी को हटा दिया गया था। लाइसेंस के आवंटन में भी खामियां मिली थीं। इस बाबत चीफ सेटरी ने एलजी को पूरी रिपोर्ट दी थी।

घोषणा : प्रारूप चार : नियम आठ

1. प्रकाशन का स्थान	**- भोपाल**
2. प्रकाशन की अवधि	**- मासिक**
3. मुद्रक का नाम	**- जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, भोपाल**
4. प्रकाशक का नाम	**- विजया पाठक**
5. क्या आप भारत के नागरिक है	**- हाँ (भारतीय)**
6. संपादक का नाम	**- विजया पाठक, भारतीय**
7. पत्र के स्वामी का नाम व पता	**- विजया पाठक, एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल**

मै विजया पाठक यह घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान ओर विश्वास के आधार पर पूर्णतः सत्य है।

1 मार्च 2023

विजया पाठक
प्रकाशक

मध्यप्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएँ

क्रांतिदीप अलूने

निरंतर बढ़ती आबादी के पोषण के लिए उसी अनुपात में फसलों का उत्पादन, कृषि गतिविधियों और खाद्य व्यापार में वृद्धि जरूरी हो जाती है। दुनिया में आबादी लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2050 तक इसके 10 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। वैश्विक कृषि बाजार वर्ष 2022 में 11 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ कर 12.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया हैं जो वर्ष 2026 तक 16.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाने की उम्मीद है। देश के दिल में बसा मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी जीएसडीपी में कृषि का योगदान 47 फीसदी है। इसीलिए मध्यप्रदेश को फ़ूड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने का गौरव मिला हैं। प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसी के मद्देनज़र प्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।

मध्यप्रदेश देश में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में जैविक उत्पादों की खेती का रकबा भी अच्छा खासा है। सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, खट्टे फल, प्याज और फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन, बागवानी, मिर्च, सुगंधित, औषधीय पौधों और दुग्ध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। शरबती गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक है। शरबती गेहूँ का आटा देश में उच्चतम गुणवत्ता वाला माना गया है।

राज्य का कृषि-जलवायु क्षेत्र 11 भाग में विभक्त है। इससे कृषि उपज में विविधता दिखायी देती है। प्रदेश में 10 प्रमुख नदी घाटियाँ और 0.3 मिलियन हेक्टेयर में फैले

अंतर्देशीय जल निकाय, 17 हजार किलोमीटर से अधिक फैली हुई नदियाँ और नहरें, 60 हजार हेक्टेयर से अधिक छोटे-बड़े तालाबों से पानी की भरपूर उपलब्धता से राज्य में कृषि उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा मिला है।

मध्यप्रदेश में बेहतर बीज गुणवत्ता के विकास, उर्वरकों, चारा उत्पादन और आपूर्ति, कृषि मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में पूँजी निवेश पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेती के क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं। साथ ही कृषि और खाद्य प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन और संबंधित डिजिटल सेवाओं को भी प्रदेश में

मध्यप्रदेश में बेहतर बीज गुणवत्ता के विकास, उर्वरकों, चारा उत्पादन और आपूर्ति, कृषि मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में पूँजी निवेश पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेती के क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं।

प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खाद्य प्र-संस्करण

मध्यप्रदेश सरकार ने मेगा फूड पार्क, कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धित अवसंरचना, खाद्य प्र-संस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने की पहल की है। कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण क्षेत्र को ?बढ़ाने के लिये भी कई कार्य किये जा रहे हैं। सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण के पीएम फॉर्मलाइजेशन की केन्द्र सरकार की पहल, राज्य उद्यमियों की क्षमता निर्माण और किसान उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों को सहायता देने, असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण उद्यमों की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। उत्पादक सहकारी समितियाँ और सहकारी समितियाँ अपनी संपूर्ण मूल्य श्रंखला के साथ सूक्ष्म उद्यमों को सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं।

वर्ष 2021 में दुनिया के खाद्य प्र-

संस्करण बाजार का आकार ₹5.7 ट्रिलियन था। इस क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 7.60 प्रतिशत की कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें एशिया प्रशांत इस क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया जैसे उभरते बाजार तेजी से वैश्विक विकास को गति देंगे। बढ़ते ग्राहक आधार के करीब होने के लिए विनिर्माण और प्र-संस्करण तेजी से इन बाजारों में जायेंगे। भारत का खाद्य उत्पादन उद्योग 400 बिलियन

पर सरकारी वित्त-पोषित फूड पार्कों की स्थापना, 2 निजी मेगा फूड पार्क और एपीसी के तहत अनुमोदित 4 कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर जैसी कई पहल की गई है। राज्य ने अपनी भण्डारण क्षमता को लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है और यहाँ 3 लाख 54 हजार वर्गमीटर की कुल सीमा के साथ एक विशाल कोल्ड-स्टोरेज हैंडलिंग क्षेत्र है।

खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने फूड

कम्पनियों को शासन स्तर से अनुकूल नीतिगत बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर निवेश को आकर्षित किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योग समर्थक नीतियाँ बनायी हैं। वित्तीय मोर्चे पर, खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र को दिया जाने वाला प्रोत्साहन राज्य के अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन का डेढ़ गुना है। राज्य ने अपने निर्यात को वर्ष 2005-06 में 83 करोड़ रुपये मूल्य के 9 हजार 600 मीट्रिक टन से बढ़ा कर वर्ष 2021-

अमरीकी डालर से अधिक का है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। यह वर्ष 2025-26 तक 535 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँचेगा। भारत की विश्व स्तर पर खाद्य उत्पादन में एक मजबूत स्थिति है और इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है।

इस परिदृश्य में मध्यप्रदेश, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग को सशक्त बनाने के लिये लगातार काम कर रहा है। राज्य में 8 स्थान

इनोवेशन हब विकसित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है। राज्य में पहले से ही 5 प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो इस क्षेत्र के लिए मूल्य श्रंखला में मौजूदा कार्य बल को शिक्षित करने और प्रतिभाशाली कौशल बल जोड़ने के लिए समर्पित हैं। मध्यप्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के प्रोत्साहनों के ईतर भी प्रोत्साहनों से उद्योगों को आकर्षित कर रही है।

मध्यप्रदेश ने हाल के दिनों में कैडबरी, आईटीसी, यूनिलीवर जैसी दिग्गज नामी

22 में एक हजार 300 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग एक लाख 43 हजार मीट्रिक टन कृषि उत्पादों को 18 प्रतिशत से अधिक के आश्चर्यजनक सीएजीआर के साथ बढ़ाया है।

एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) योजना में मध्यप्रदेश ने 24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पादों की पहचान की है। कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/साइट्रस, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी

मटर, मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया, सरसों के उत्पाद, गन्ना उत्पाद, आँवला और हल्दी इसमें शामिल हैं। संतरे का उत्पादन प्रदेश को संतरा प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए आदर्श बनाता है। प्रदेश में बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले में आम आधारित कई खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित होने के विभिन्न चरण में हैं।

राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों की जलवायु और क्षमताओं के आधार पर किसानों को ऐसी उपज लगाने के लिये प्रोत्साहित किया है जिससे रस, जैम, स्क्वैश, सिरप, सौंदर्य उत्पाद, इत्र, आवश्यक तेल, लुगदी, सूखे आम पाउडर, चटनी, आम जैसे प्र-संस्कृत खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है।

खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र के अलावा, डेयरी गतिविधियाँ मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन भी है। ज्यादातर डेयरी उत्पाद दूध के रूप में बेचे जाते हैं। इसलिये इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन और समग्र डेयरी प्र-संस्करण की जबरदस्त संभावनाएँ मौजूद हैं। वर्तमान में तरल दूध का हिस्सा राज्य के कुल बाजार हिस्सेदारी का 48 प्रतिशत है। सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में दही, पनीर, यूएचटी दूध, फ्लेवर्ड दूध और छाछ शामिल हैं।

मध्यप्रदेश तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का 8.6 प्रतिशत का योगदान है। मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन- शीर्ष निकाय एमपीसीडीएफ की अकेले 9 लाख 13 हजार केजीपीडी की औसत दूध खरीद दर्ज की गई है। डेयरी प्र-संस्करण में शामिल प्रमुख कंपनी-उपक्रमों में अमूल साँची, अनित इंडस्ट्रीज सौरभ और पवनश्री फूड इंटरनेशनल शामिल हैं। कुल मिलाकर राज्य में समग्र कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में निवेश के भरपूर अवसर है।

कम्पलीट बिजनेस साल्यूशन वाले फ्यूचर रेडी स्टेट मध्यप्रदेश में निवेशकों का बढ़ा रूझान

बबीता मिश्रा

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को कंपलीट बिजनेस साल्यूशन के साथ फ्यूचर रेडी स्टेट बनाने से प्रदेश में निवेश के लिए देश-विदेश के निवेशकों का रूझान बढ़ रहा है।

यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिये शासकीय अनुमतियों से लेकर इंडस्ट्री प्रारंभ करने के बाद उसके सफल संचालन के लिये आवश्यक सभी सुविधाएँ आसानी से प्राप्त हो जाती हैं।

भारत में निवेश के लिए सर्वोत्तम राज्य

क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश भारत का हृदय है और आज ये सबसे तेज गति से विकास पथ- पर अग्रसर है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से संपन्न है। राज्य में 95 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 7 स्मार्ट सिटी और बेहतरीन यातायात व्यवस्था है।

राज्य में खेती एवं प्रोसेसिंग क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जिससे औद्योगिक निवेश के लिए माहौल बन रहा है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, टेक्सटाईल, लॉजिस्टिक, आईटी, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, शहरी विकास ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ निवेश की अपार संभावनाएँ हैं।

राज्य में कुशल मानव संसाधन और उचित मूल्य पर भूमि की उपलब्धता, राज्य में औद्योगिक वातावरण को तैयार करती है। सरकार की नीति और प्रशासन का सहयोग इस दिशा में मददगार साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वह सभी कुछ है, जो निवेश के लिए आवश्यक है।

विश्व-स्तरीय कनेक्टिविटी

देश के केंद्र में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश की सीमा देश के 5 राज्यों से लगती है और यह देश की तकरीबन 50 प्रतिशत आबादी को प्रवेश देता है। यह देश के किसी भी उपभोक्ता बाजार से अधिकतम 15 घंटे की दूरी पर स्थित है। भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में कुल 5 कॉमर्शियल हवाई अड्डे हैं। 20 से अधिक रेल जंक्शन और राज्य में 550 से अधिक ट्रेनें संचालित होती है। मालनपुर, मंडीदीप, पवारखेड़ा, रतलाम, तिही, धन्नद में 6 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं।

मध्यप्रदेश देश के कई बड़े प्रोजेक्टस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत मध्य प्रदेश के हिस्से में औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन आया है। नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के लिए

साथ विकसित दिल्ली- नागपुर कॉरिडोर से आर्थिक गतिविधियों में आश्चर्यजनक रूप से उछाल आएगा। ग्वालियर से होकर जाने वाले ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (एन.एच.27) को उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए मध्यप्रदेश का गेटवे कहा जाता है। दिल्ली-मुम्बई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के प्रदेश से गुजरने के कारण प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ गई है और औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है। रतलाम- दिल्ली-मुम्बई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का केंद्र है।

म.प्र. में उद्योग के प्रमुख सेक्टर्स का हुआ विकास

मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर्स का चुनाव किया है, जो सरकार की 550 बिलियन अमरीकी डॉलर अर्थ-व्यवस्था की सोच को साकार करने में सहयोग करेंगे।

ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेक्टर

ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 10 से अधिक उपकरण निर्माता और 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माता कार्यरत हैं। इन्दौर और भोपाल में भारत के अग्रणी ऑटो क्लस्टर्स हैं। पीथमपुर में 4500 हेक्टेयर में विकसित औद्योगिक क्लस्टर 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। इंदौर में एशिया का सबसे लंबे और तेज गति के टेस्टिंग ट्रेक नेट्रेक्स की स्थापना की गई है।

फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि सेक्टर

मध्यप्रदेश को भारत का फूड बास्केट कहा जाता है। यहाँ 45 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है, जो 10 प्रमुख नदियों से जुड़ी है। इस वजह से जिसके कारण राज्य में उत्तम सिंचाई व्यवस्था है। प्रदेश उद्यनिकी फसलों, मसालों, संतरा, अदरक, लहसुन आदि के उत्पादन में अग्रणी है। मध्यप्रदेश दलहन, तिलहन एवं डेयरी उत्पाद में भी अग्रणी है। राज्य में 8 सरकारी फूड पार्क और 2 निजी मेगा फूड पार्क है। इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर में सरकारी कृषि कॉलेज संचालित हैं। प्रदेश को 7 बार भारत सरकार से कृषि क्षेत्र का प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार मिलना प्रदेश की उन्नत कृषि का संकेत है।

टेक्सटाईल एवं गारमेंट सेक्टर

मध्यप्रदेश में टेक्सटाईल एवं गारमेंट सेक्टर में भी सतत् प्रगति हो रही है। राज्य 43 प्रतिशत भारतीय और 24 प्रतिशत वैश्विक जैविक रूई का उत्पादक है। यहाँ 60 से अधिक टेक्सटाईल यूनिट में 4 हजार से अधिक लूम्स और 2.5 मिलियन स्पिंडल्स संचालित हैं। राज्य के टेक्सटाईल सेक्टर में स्पिनिंग से लेकर बुनाई, गारमेंटिंग की सभी प्रक्रिया रूप से संचालित हैं। भारत सरकार की पीएलआई योजना में राज्य के टेक्सटाईल सेक्टर को 3513 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। गारमेंट यूनिट के प्लांट एवं मशीनरी में निवेश का 200 प्रतिशत तक का पॉलिसी इंसेंटिव दिया जाता है। प्रदेश में 200 से अधिक रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर एवं इन्दौर में अपैरल डिजाइनिंग सेंटर स्थित है।

एनआईएफटी, एनआईडी भोपाल और आईआईआईटीडीएम जबलपुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट मध्यप्रदेश के टेक्सटाईल उद्योग की रीढ़ हैं।

फार्मास्यूटिकल सेक्टर

मध्यप्रदेश में फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में यहाँ की दवाइयाँ विदेशों में निर्यात की गईं। इन्दौर, देवास, भोपाल, मंडीदीप, मालनपुर और पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फार्मा क्लस्टर है। यहाँ 300 फार्मा एवं मेडिकल यूनिट से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है। साल 2021 में राज्य से 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का फार्मा निर्यात किया गया। अमेरीका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ब्राजील, हॉलैंड सहित विश्व के 160 से अधिक देशों में राज्य में बनने वाली दवाइयाँ निर्यात की जा रही हैं। राज्य को एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त 73 फार्मेसी इंस्टीट्यूट से 9 हजार से अधिक स्किल्ड प्रोफेशनल प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहे हैं। फार्मा सेक्टर के विकास और क्षमता को देखते हुए प्रदेश में फार्मा औद्योगिक पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग सेक्टर

मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग के लिए आदर्श सड़कें एवं रेल कनेक्टिविटी है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक का खर्च बेहद कम है। देश की 50 प्रतिशत आबादी मध्यप्रदेश से जुड़ी हुई है। इससे विशाल उपभोक्ता बाजार पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रदेश में 40 एमएमटी की वेयरहाउसिंग और 13.2 एमएमटी की कोल्ड स्टोरेज क्षमता है। भारत सरकार के सहयोग से इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश स्टील साइलो निर्माण के क्षेत्र में भी अग्रणी है। प्रदेश में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग इकाई / पार्क के लिए आकर्षक इंसेंटिव पॉलिसी है।

अक्षय ऊर्जा सेक्टर

मध्यप्रदेश अक्षय ऊर्जा के सृजन लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य की अक्षय ऊर्जा की क्षमता साल 2012 की तुलना में 11 गुना बढ़ गई है। सर्वाधिक सोलर रेडिएशन के कारण राज्य सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान है। तकनीकी रूप से मजबूत अक्षय ऊर्जा पॉलिसी बनाकर अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण और इनोवेशन करने वाला पहला राज्य है। अक्षय ऊर्जा का मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में 20 प्रतिशत का योगदान है। साँची को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर

पार्क (600 मेगावाट) ओंकारेश्वर में प्रस्तावित है। रीवा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसीडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

रक्षा क्षेत्र एवं एयरोस्पेस सेक्टर

मध्यप्रदेश रक्षा उपकरण निर्माण के लिए आदर्श राज्य है। यहाँ रेअर अर्थ मेटल प्रोसेसिंग, अनुसंधान एवं विकास ट्रेनिंग के लिए भोपाल में रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम प्रस्तावित है। राज्य में 4 पीएसयू जबलपुर और 1-1 पीएसयू कटनी और इटारसी में है। प्रदेश में भारत की पहली निजी क्षेत्र की लघु हथियार निर्माण यूनिट स्थापित की गई है। 5 कॉमर्शियल हवाई अड्डे तथा भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डे एमआरओ गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ इंडस्ट्री एवं सिविल हवाई सेवा के लिए 26 एयर स्ट्रिप हैं। मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन के साथ इंदौर के समीप ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है।

आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम सेक्टर

राज्य में 150 से अधिक ईएसडीएम यूनिट और 220 से अधिक आईटी/आईटीईएस यूनिट मौजूद हैं। राज्य में 4 स्पेशल आईटी इकोनॉमिक जोन, 10 आईटी पार्क, 2 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मौजूद हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में हर तरह की सुविधाओं से युक्त बुनियादी ढाँचा है। राज्य में आईआईटी, आई आई एम, आई आई एसाई आर, आईआईटीएम जैसे 330 से अधिक तकनीकी इंस्टीट्यूट स्किल्ड प्रोफेशनल को तैयार कर रहे हैं। राज्य में जीवन जीने के लिए बेहतरीन माहौल उपलब्ध है। इन्दौर और भोपाल देश के 10 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हैं। उचित दर पर 24x7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुविधा है। यहाँ लो रिस्क सीस्मिक जोन के कारण डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए आदर्श स्थिति है।

मध्यप्रदेश स्टार्ट अप इकोसिस्टम

मध्यप्रदेश की स्टार्ट अप पॉलिसी 2022 के तहत राज्य में स्टार्ट अप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पाद आधारित स्टार्ट अप को विशेष सहायता दी जा रही है। हर तरह के आर्थिक सहयोग और जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। राज्य में 2500 से अधिक डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप्स और 45 से अधिक इनक्यूबेटर सेंटर स्थित है। महिला उद्यमियों द्वारा 1100 से अधिक स्टार्ट अप संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में 26 लाख से अधिक एमएसएमई इकाईयाँ हैं जिनका राज्य की जीडीपी में 25.68 प्रतिशत योगदान है।

कैसे होगी महंगाई कम?

डॉ. सत्यनारायण सिंह

अर्थशास्त्रियों के अनुसार आपूर्ति व मांग के समीकरण बिगड़ने से महंगाई बढ़ती है। गत वर्षों में विश्वव्यापी मंदी, उपभोक्तावाद में वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव घटने-बढ़ने से पेट्रोल व डीजल की अस्थिर कीमतें देश में लगातार बढ़ती मंहगाई के प्रमुख कारण हैं, परंतु अब राजनीति एवं अर्थनीति से भी कीमतें तय हो रही हैं।

प्रतिदिन यह देखा जा रहा है कि सेंसेक्स कितना बढ़ा, निफ्टी कितनी बढ़ी, सोना और चांदी के भाव कितने घटे-बढ़े। जिन चीजों में भी सरकार और राजनीति का दखल है, सब महंगी होती जा रही है। थोक बाजार में यदि कुछ वस्तुओं के दामों में कमी होती है तो महंगाई कम होने का राग अलापना प्रारंभ हो जाता है। उपभोक्ता मूल्यों की तरफ और मूल भूत आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों पर सरकारें मौन रहती हैं। न उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान है, न सप्लाई बढ़ाने की तरफ ध्यान है न अवैध रूप से संग्रहण करने वालों व काला बाजारियों पर कोई अंकुश है, और न ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु किया जा रहा है।

सरकार ने गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमत नियंत्रण से रोक हटा कर इसे उत्पादकों पर छोड़ दिया। सरकारें कहती हैं कि वे आम उपभोक्ता के साथ हैं, जबकि स्पष्टता वह पूंजीपतियों व बड़े उद्योगपतियों के साथ है। निजी क्षेत्र के दायरे की वस्तुएं मोबाईल फोन से लेकर कार व हर चीज जिनका निर्माण निजी क्षेत्र में हो रहा है, उनकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में लगातार जबर्दस्त कमी हो रही है। उम्मीद थी कि उसी के अनुरूप पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में भी कमी आयेगी, परंतु सरकार ने कीमतों में मामूली कमी की। जिस अनुपात में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटे थे उसके मुकाबले की गई कमी ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार ने एक माह में तीन बार पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि कर दी। राज्य सरकारों ने भी कर नहीं घटाया व वैट बढ़ा दिया और इस प्रकार खजाना भरने का जुगाड़ कर लिया। केन्द्र सरकार को आर्थिक घाटे को पाटा था, 60 प्रतिशत क्रूड आयल के भाव कम हो गये, लेकिन सरकार ने डीजल में मात्र 8 प्रतिशत और पेट्रोल में मात्र 13 प्रतिशत राहत दी। इस कमी के बाद भी यातायात साधनों (रेल, बीस किराया) व मालवाहक किराये में कमी नहीं की गई और जनता को भारी मूल्य गिरावट से कोई लाभ नहीं

मिला।

सरकार प्रचारित कर रही है कि मुद्रास्फीति कम हुई है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि महंगाई कम हो गई। मंहगाई की दर कागजों में ज्यादा गिरी, हकीकत में नहीं। डीजल का उपयोग रेलवे, राज्य परिवहन सेवाओं व ट्रांसपोर्टो द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है, परंतु जनता को डीजल की कीमतों में गिरावट का लाभ नहीं मिला। मूल्य में जो गिरावट आई है, वह सरकार के सार्थक प्रयासों से नहीं, मौसम की वजह से हुई है। अब एसोचेम ने सिफारिश कर दी कि जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल-पेट्रोल की कीमत कम हुई है उसका लाभ उपभोक्ताओं को न देकर पेट्रोल-डीजल के उत्पादन कार्यों में लिए जाए। भारत में तेल कम्पनियों की मोनोपाली है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए भी उपभोक्ता को फायदा नहीं हो रहा है। दो बार उत्पादक शुल्क वृद्धि से ही सरकार को सालाना 40 हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा। अब तो सरकार ने डीजल-पेट्रोल का डी-कन्ट्रोल भी कर दिया है और सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार राजकोषीय घाटा कम करने में लगी है। दूसरी ओर सरकार आरबीआई से ऋणों पर ब्याज दर कम करवा रही है। उससे निजी उपभोग, वाहन व आवास ऋण बैंक अधिक मात्रा में देंगे, मांग बढ़ेगी और कीमतें बढेंगी। तेल के खुदरा दाम सीधे अन्तर्राष्ट्रीय भाव से जुड़े नहीं रखे जा रहे हैं। रियल एस्टेट में तो डीएलसी रेट बढ़ने, निर्माण सामग्रियों की कीमतें बढ़ने व भूमाफियों का कालाधन लगने से मकानों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए ही बैंक दर कम करने की मांग की जा रही है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने चावल, गेंहू के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाये, भण्डारण किया, परंतु कीमतों पर काबू पाने के लिए भण्डारण का

उपयोग नहीं कर रही है। चीनी का उत्पादन कितना किया जाए, कितना आयात किया जाए, कितना निर्यात किया जाए, बिक्री की कीमत क्या हो? यह सरकार तय करती है। लागत से मूल्य का कोई रिश्ता नहीं है। खाद्य तेल व दालों का उत्पादन बढ़ाने का भी विशेष प्रयास नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। फल और सब्जियों के उत्पादन में कमी नहीं है फिर भी खेत से लेकर थाली तक आपूर्ति श्रृंखला की व्यवस्था मौजूद नही है।

जरुरी चीजों की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। चावल की कीमतें 130 प्रतिशत तो चीनी की 193 प्रतिशत और दालों की 250 प्रतिशत तक बढ़ी। वेट समाप्त नहीं किया गया। जमाखोरी की धर-पकड़ नहीं की गई।

यह सही है कि वैश्विक महंगाई से आपूर्ति में कमी हुई। खानदान की बदलती आदतों से मांग बढ़ी, परंतु यह भी सच्चाई है कि जमाखोरी पर रोक लगाने व भण्डारण की सीमा निर्धारित करने का समान कानून नहीं बना। समय-समय एडवान्स में राजनेताओं के भ्रामक बयानों से भी व्यापारियों और जमाखोरों को पहले ही संकेत मिल जाता है। खुदरा क्षेत्र में सुधार न करने के कारण अधिकांश फल व सब्जियां बर्बाद होती है। नाफेड जैसी एजेंसियां भी फेल हो गई हैं। किसानों की असली समस्याओं को हल करने तथा उत्पादन में सुधार करने के लिए कोई तत्परता नहीं बरती गई। अब भारत में कीमतें मांग और आपूर्ति के अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों से नहीं, राजनीति से तय होने लगी हैं। आपूर्ति प्रणाली के अवरोध एवं कमजोर वितरण ढांचे को दुरुस्त करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। कीमतों का प्रबंधन, नाम की कोई चीज नहीं है। बिचैलियों की चांदी है। स्पष्ट है समग्र सुधारों, राजनीतिक इच्छाशक्ति कठोर प्रबंधन के बगैर महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। कुछ गलती जनता की भी है। वह अनावश्यक दाम बढ़ाकर विक्रय करने वालों को प्रोत्साहित करती है न कि हतोत्साहित। आजादी के बाद से अब तक यह अनुभव रहा है कि चाहे कांग्रेस सरकार हो या मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार, प्रगति, विकास और खुशहाली के एजेण्डों में महंगाई की रोकथाम के लिए व्यापक एवं मजबूत कदम नहीं उठाये गये।

श्रमिकों के लिए अभी बहुत कुछ करना है

समता पाठक

श्रम की हमेशा पूजा हुई है लेकिन श्रम करने वालों को वह स्तर नहीं दिया जा सका जिसके वे हकदार हैं। आज भी हम जब रिक्शे पर बैठते हैं तो रिक्शा चालक की मेहनत देखकर लगता है कि उसको प्रतिफल नहीं मिल रहा है। छोटी-छोटी चाय की दुकानों, ढाबों पर काम करने वालों के बारे में जब पता चलता है कि मामूली सी पगार मिल रही है तो तकलीफ होती है लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकार आज तक नहीं मिल पाये हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि श्रमिकों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा दी जा रही है लेकिन कुछ लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। पहली मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में भी इस दिन को श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसका बढ़ चढ़ कर प्रचार किया जाता है। आगे क्या करना है, इसकी जानकारी दी जाती है। बाद में सब कुछ वैसे का वैसा ही चलता रहता है। अभी पिछले दिनों केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने मई दिवस के मद्देनजर ही कम से कम एक हजार रूपये की पेंशन जारी रखने का फैसला किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सूची तैयार करने की बात भी कही गयी हे। अभी हमें

यह पता नहीं है कि हमारे देश में कितने संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और कितने असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दोनों ही क्षेत्रों में काम करने वालों को पूरे अधिकार नहीं मिल पाये हैं। बिहार में सवर्ण कमेटी की रिपोर्ट ने इस भ्रम को भी दूर कर दिया है कि गरीबों में सिर्फ निम्न जाति के लोग शामिल हैं बल्कि सवर्णों में भी गरीब और कामगार ज्यादा हैं। यही स्थिति अन्य प्रदेशों की भी है। कामगारों अर्थात श्रमिकों के बारे में अभी काफी कुछ करना बाकी है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि केन्द्र से राज्य तक इस प्रकार के प्रयास किये गये जिससे कामगारों की सामाजिक आर्थिक

स्थिति सुधर सके। इस मामले में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को भी श्रेय मिलना चाहिए जिसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लागू किया। इस योजना के बाद ग्रामीण स्तर पर काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी तय की गयी। इससे पहले नाममात्र की मजदूरी पर लोग काम करवाते थे। शहरों में मजदूर मंडी लगती है और वहां गावों की अपेक्षा ज्यादा मजदूरी भी मिल जाती है। इससे गांव छोड़कर लोग शहरों में मजदूरी करने आते हैं। इनकी संख्या अब कम हो रही है। इसी प्रकार श्रमिकों के संगठन भी बनने लगे हैं। रिक्शा चालकों का संगठन बना है तो टेम्पो चालक भी यूनियन बनाये हुए हैं। फुटपाथ पर दुकान लगाकर या ठेले पर सामान बेचने वाले भी संगठित किये जा रहे हैं। इनको शोषण से बचाने का प्रयास भी होता है। पटरी दुकानदारों को लाइसेंस दिया जा रहा है। सरकारी स्तर पर भी संविदा पर कर्मचारी भर्ती किये जाते हैं। उनके लिए श्रम के घंटे, मजदूरी और अन्य सुविधाएं भी तय कर दी गयी हैं। मजदूरों ने जिस संघर्ष की याद में मई दिवस मनाना शुरू किया था, उसकी अपेक्षा वर्तमान में काफी सुधार दिखाई पड़ता है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तो अच्छा वेतन भी मिल रहा है। इसी क्रम में सरकार ने भविष्यनिधि खाते से ही पेंशन की दर तय कर दी है। ईपीएफओ के तहत न्यूनतम 1000 रूपये मासिक पेंशन देने की योजना मंजूर की है। इससे 20 लाख लोगों को फायदा होगा।

सबसे ज्यादा काम अभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ही करना है। दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वालों से लेकर ईंट, भट्टा मजदूरों और होटल ढाबों पर काम करने वालों का एक ब्योरा रखना जरूरी है। इनको शोषण का शिकार न होना पड़े, इसलिए सरकार के पास सटीक जानकारी होनी चाहिए। कभी-कभी इनके साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और मालिक द्वारा इनका इलाज भी ठीक से नहीं कराया जाता। सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करना होगा कि मजदूरी करने वाला अपने सभी अधिकार ठीक से प्राप्त कर सके। दिल्ली में अरबिन्द केजरीवाल की सरकार ने चुनाव पूर्व यह वादा भी किया था। इसलिए वहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण कराया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाई अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए। हालांकि इनकी संख्या घटती, बढ़ती रहती है। इसके अलावा कभी-कभी अराजक और असामाजिक तत्व भी इनके बीच शामिल हो जाते हैं जिससे पूरे देश की

बदनामी होती है। पुलिस की नजर में तो ये संदिग्ध हो ही जाते है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार कारपोरेट घरानों की ज्यादा पक्षधर है। इस में कुछ सच्चाई तो है क्योंकि श्री मोदी देश की आर्थिक विकास दर बढ़ाना चाहते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून की इसीलिए आलोचना की जा रही है क्योंकि इसके इर्द गिर्द के लिए भूमि अधिग्रहित करना आसान होगा। मोदी ने मेक इन इंडिया का अभियान शुरू कर रखा है। इसलिए मजदूरो की अपेक्षा मालिकों को सुविधाएं देने की कोशिश हो सकती है। इससे मालिकों में मजदूरों का शोषण करने की प्रवृत्ति भी पैदा हो सकती है। हरियाणा का एक उदाहरण इसके लिए पर्याप्त है। तत्कालीन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गुड़गांव में हीरोहांडा कम्पनी के मालिकों के दबाव में ही मजदूरों पर लाठीचार्ज करवा दिया था। इतना ही नहीं कई मजदूर अभी तक जेल में बंद हैं। मुख्य कारण यह कि गुड़गांव को इंडस्ट्रियल हब बनाना था।

इसलिए मोदी सरकार को भी याद रखना चाहिए कि औद्योगिक विकास के लिए सिर्फ मालिकों का हित न देखा जाए बल्कि मजदूरों का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाए। श्रमायुक्त और उपश्रमायुक्त कार्यालयों की जिम्मेदारी का ही नतीजा है कि कितने ही कल-कारखाने बंद हो गये और मजदूर बेरोजगार हो गये। उत्तर प्रदेश में भारत का मानचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर उद्योगों के मामले में कितना पिछड़ गया है। पश्चिम बंगाल में, जहां ट्रेड यूनियन की राजनीति ही सत्ता की राजनीति बन गयी थी, वहां भी मजदूरों के हितों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए श्रम दिवस पर यह संकल्प ही नहीं लेना होगा कि मजदूरों का कल्याण करना है, बल्कि उस दिशा में ठोस कदम भी उठाने होंगे। श्रम का महत्व तभी है जब उसकी कद्र की जाए श्रमिकों की दशा ठीक रहेगी तो विकास के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे।

Public Relations in Banking Sector

Public Relation (PR) is the most important and essential part of the communication. British Institute of Public Relation defined PR as a planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its public. According to American Institute of PR, Public Relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organization and their public. On the other way, it is an important method for image building, to maintain goodwill and publicity of an organization to win over an extremely competitive market. A favarable image or good reputaion helps to increase the sale of a particular company and in case of negetive publicity, the company's sale as well as its reputation will be at stake. So, to enhance a company's reputation, several methods are practiced by the practiced by the PR department to communicate with the internal and external public. It is a two-way flow of mutual understanding (Sam

Black, Practical Public Relations). It is an extended arm and eyes and eard of modern way of management.

The concept of Public Relation dates back to history. In 49 BC reports about the achievements of Julius Caesar was published in a daily, 'Acta Diurna'. In 1066 the Norman conques of England was depicted in worls's first info-graphic, the Bayeuk Tapestry. In 17th century the term 'propaganda' was first used by the Catholi Church. In an address to US congress Thomas Jefferson first used the term 'public relation' in 1807. But, the first PR department was established in 1889 by Westinghouse. It was established to fight Thomas electric. This is known as the 'battle of currents'. The term PR was first used in the year-book of railway literature (1897) to communicate between the public and their organization. This is marked as the birth of the Public Relation. The first Public Relations agency, namely 'The Publicity Bureau' was established in 1900.

The first official release was created by Ivy Ledbetter Lee in 1906. It was created on electric train wreck. This was printed in 'The New York Times'. Lee was na American publicity expertand considered as the founder of modern Public Relation and became popular for his work with

the Rockefeller family. In 1924 Basil Clark introduces PR in Britain. When wall Street craches in 1929, Public Relatons became a necessity. Edward Louis Barnes was an Austrian-American expert in the field of Public Relatons. He was best known for to encourage female smoking by branding cigarettes with the 'Torches of Freedom'. He was the pioneer in the field of propaganda and worked for leading American corporate companies like 'Procter and Gamble; 'General Electric; In his obituary (10th March, 1995), 'The New York Times referred him as 'The father of Public Relations and leader in opinion making'.

Evolution of PR in India was found in our epics Ramayana and Mahabharata. The administration was very much concerned about their public feelings and opinions. India had master of religious communicators like Gautama Buddha, Shankaracharya. King Ashoka sent his daughter Sanghamitra to Sri Lanka to preach Buddhism. She is known as the first female PR executive in History. Ashokan inscriptions were an indeal example of Public Relations. Systematic practice of PR began with the House of Tata's and by India Railways. After independence, the Government set up different media units to handle Public Relations.

Role of PR in banking sector

PR is considered as a very crucial and vital part of banking sector for image building, to maintain goodwill and to gain trust of its customers. In case of banking, for their daily transaction customers need interaction with their respective banks. Besides, banks have to inform about their different schemes and facilities to the customers. So, the public relation or customer care department has to play a vital role in entertaining and fulfilling the need of the same. To gain the trust or confidence of its customers, banks need PR support. PR department often do research rgarding customer

satisfaction about different bankking schemes and products.

Different methods or tools are used by banks. The traditional methods are by sending News or Press release to different media, Newsletters to the customers and by appearances at public events, such as, trade show, conventions etc. With the advancement of the modern technology, banking service has now been exposed to our fingertips. PR department can now use internet as a medium of communication. Social media, e-mail, and text messgages are sed to accomplish their goals.

Banking industry is a service orientetd one Community banks know the imprtance of public consent. So, sevral services are offered to satisfy the need of a customer.Besides, debit and credit cards and net banking is becoming more and more popular now. Phone banking has also made the transactions very. People can access their accounts also through banking apps. Nowadays, it is very easy to get a loan for buying a car or house or to vail a loan for education or to start a new venture. PR in banks works for 24x7 to maintain a good relation with its customers. People can have financial transactions or enquire about a particular service through attractive and useful websites.

Brand ambassadors also play na important role to build a positive image about a particular bank; for example, Deepika Padukone is the brand ambassador for Axis Bank from 2014 and Amitabh Bachchan was the brand ambassador for ICICI bank in 2013-14 ICICI bank has also used the bollywood superstar Shahrukh khan to boost their overseas business.

Bank of Baroda once used leading Indian cricketer Rahul Dravid in 2005. Dravid symbolizes solidity and trust. IndusInd bank prefereed actors like Farhan Akhtar, Sharman Joshi and Boman Irani rather than stars. Joshi featured in a service called 'My Account, My Number' to get account numbers as per the choice of the

customers. In 2016, Boman Irani and Farhan Akhtar advertise for a new service called 'fingerprint Banking' to allow customers to make transactions on its mobile banking app. Captain of India cricket team, Virat Kohli is associated with the Punjab National Bank since he was 16. Canara bank had chosen the India opener Shikhar Dhawan as their brand ambassador in 2014. Among foreign bank, Royal Bank of Scotland roped in master blaster Sachin Tendulkar in 2008 as their brand ambassador. In 2003 Standard Chartered Bank selected ex-India captain kapil Dev as a face for their campaign. In 2006 renowned Cricket Sunil Gavasker joined tennis star Sania Mirza as the brand ambassador of Deutsche Bank.

PR department not only enhances communication and publicity, but also have a pivotal role in crisis management. Routine jobs of PRO do not need a very innovative mind; in fact it is not a very interesting genre. But, in the crisis situations, it is totally different. It is then and only then that the PRO becomes the judge, crisis situation are an acid test for the PRO. The Public Relation is to deal with anything and everything that they have to face in the crisis situations. Thers is no fixed crisis and therefore there is no particular formula to combat a crisis in a crisis situation. However, there are some basic ways to get going. One must be prepared for the worst and hope for the best. In the crisis situation Public Relations department of an organization has to deal with the major unpredictable event. It is said that when in crises, we must tell the truth and act promptly.

The three C's of credibility are to be-compassionate, competent and confident.

For better communication with the public bank have changed a lot. ICICI bank which is the second largest bank of India, Introduced 'Branding' in the Idian banking industry. They first introduced net banking and e-mail marketing. They are the pioneers in retail banking and emphasizes on the data entre availability and data protection solution. For better customer relation 'MILAP' function is conducted on the third Friday of every month to get feedback from the customers. The outdoor activity also increased from time to time. Besides that they also took several measures to keep in constant touch with their internal public. They also involved themselves in film promotion, as in 'Baghban' (2003)

To launch international credit card, ICICI bank associated them with Amway India. So, customers can purchase Amway products from Amway distributors to redeem their points. Again, ICICI customers can book railway tickets by using mobile banking system. ICICI Bank also tie-up with the Cartoon Network for theif publicity purpose. IDBI and Exim Bank also financed 50% of their budget for film funding. They invested in the films like Aakhen (2002), Qayamt (2003) Main Prerm Ki Deewani Hoon (2003), Veer Zara (2004), Mangal Pandey (2005) Don (2006) etc, at present, IDBI and Exaim bank have temporily decided not to finance in film industry, but Yes Bank have continued to invest in the same for their profit & publicity. On the other hand State Bank of India one of the leading nationalized banks of India prefers to maintain customer relation by using different media channels to promote their different services and to gain credibility among its public. In the age of social media and internet technology, Public Relation of banks has now become a very effective and easier way to communicate with their respective customers.

Ph.D Research Fellow,
Department of Journalism and Mass Communication, University of Calcutta.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.